



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2023 ई० (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत) [संख्या-32

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग विधे गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु०
सम्पूर्ण गजट का नूल्य	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	837-849	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल भूमोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	299-318	1500
भाग 2—आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केंद्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइल एरिया, टारन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निवेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4—निवेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन लॉफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	461-486	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड-पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग—2

कार्यालय-ज्ञाप

21 जुलाई, 2023 ई०

संख्या 523 ई०प०—28344 / VII-A-2/2023/02(4)2022—राज्यपाल, औद्योगिक विकास अनुभाग—2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—5 / ई०प०—2844 / दिनांक 31 जनवरी, 2023 के क्रम में राज्य में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति, 2023 के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश / परिचालन दिशानिर्देश बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्—

उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति—2023 के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश

मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया

राज्य में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे नवीन और विद्यमान उद्योगों को समर्थन प्रदान करने, मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, विद्यमान लॉजिस्टिक्स बुनियादी द्वांचे के सुदृढ़ीकरण, रोजगार के अवसरों के सुजन, लॉजिस्टिक्स सूचकांक में राज्य की रैंकिंग को बढ़ाने तथा वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग—2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—85 / ई०प०—28344 / VII-A-2/2023/02(4)2022 दिनांक 31 जनवरी, 2023 से उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति—2023 प्रख्यापित की गयी है। इस नीति के क्रियान्वयन एवं नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु योजना के दिशानिर्देश / मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया निम्नवत् हैं:

1. दिशानिर्देशों की अवधि:

यह दिशानिर्देश उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति, 2023 के प्रवृत्त रहने अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधित फिये जाने की सीमा तक वैध होगे।

2. दिशानिर्देशों का अधिकारिता क्षेत्र

इन दिशानिर्देशों का अधिकारिता क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

3. दिशानिर्देशों के परिचालन/क्रियान्वयन हेतु प्राधिकृत विभाग:

दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन/परिचालन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड उत्तरवादी होगा।

4. परिभाषा:

(1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस दिशा-नीर्देशों में—

क. अधिनियम से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है।

ख. प्राधिकृत समिति से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित जिला/राज्य प्राधिकृत समिति अभिप्रेत है।

ग. प्राधिकृत अधिकारी से उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति, 2023 के क्रियान्वयन हेतु उद्योग विभाग के स्तर पर नामित अधिकारी अभिप्रेत है।

घ. राज्य स्तरीय समिति से प्रस्तर-१ में वित्तीय प्रोत्साहनों के आवेदनों पर निर्णय हेतु गठित समिति अभिग्रह तैयार है।

(2) उन शब्दों और पदों, के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक नीति, 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो उस नीति में हैं।

5. वित्तीय प्रोत्साहन:

क.	सामान्य लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए पूँजीगत उपादान	
i.	रु. 50 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए, सहायिकी (समिक्षा) की अधिकतम सीमा रु. 8 करोड़ होगी।	
ii.	रु. 50 करोड़ से अधिक और 150 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत के लिए, सहायिकी (समिक्षा) रु. 24 करोड़ तक सीमित होगी।	
iii.	रु. 150 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत के लिए, सहायिकी (समिक्षा) रु. 32 करोड़ तक सीमित होगी।	
प्रक्र.	अर्ह गतिविधियां/ क्रियाकलाप	मानदण्ड
i.	गोदाम की (व्यवहारिक्षण) सुविधायें	पर्यावरण क्षेत्र (श्रेणी ए, बी, बी+ और सी) में न्यूनतम रु. 2.5 करोड़ निवेश के साथ 5,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में गोदाम की सुविधा और गैर-पर्यावरण क्षेत्र (श्रेणी-डी) के लिए रु. 5 करोड़ के निवेश के साथ न्यूनतम 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल।
ii.	ट्रक टर्मिनल	रु. 5 करोड़ के निवेश और 45,000 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल में सीमित ट्रक टर्मिनल।
iii.	परिवहन/ट्रक मालिक/फ्लीट अपरेटर/एग्री�ेटर	कम से कम 3 ट्रक/छोटे ट्रक/मिनी पिकअप ट्रक/रेफर वैन की खरीद (एक्स-शॉर्लूप कीमत)।
iv.	कोल्ड स्टोरेज	6,000 वर्ग फुट का न्यूनतम क्षेत्रफल।
v.	बुनियादी सुविधायें	बुनियादी सुविधाओं के रूप में विकसित आंतरिक परिवहन प्रणाली, बिजली लाइन, संचार सुविधाएं, जल वितरण और जल वृद्धि सुविधाएं, सीधेज और जल निकासी लाइनें, अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाएं, फायर टैंडर व्यवस्था, पार्किंग, वेहेंग बिज, चिकित्सा केंद्र।
		परियोजना लागत का 20 प्रतिशत
		परियोजना लागत का 20 प्रतिशत
		वडे पर 10 प्रतिशत और छोटे और मध्यम ट्रकों पर 15 प्रतिशत, अधिकतम रु. 10 लाख
		परियोजना लागत का 15 प्रतिशत केंद्रीय सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रदान की जाने वाली सहायिकी (समिक्षा) के अतिरिक्त दिया जायेगा।
		परियोजना लागत का 20 प्रतिशत

टिप्पणी: उपरोक्त सभी गतिविधियों/क्रियाकलापों के लिए पूंजीगत उपादान की अधिकतम मात्रा/सीमा क्रम संख्या— ५(क)(i), (ii), (iii) में अंकित परियोजना लागत के अध्यधीन रहेगी।

ख. विशेष लॉजिस्टिक्स इकाईयों के लिए पूंजीगत उपादान:

- i. रु. 50 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी की अधिकतम सीमा रु. 8 करोड़ होगी।
- ii. रु. 50 करोड़ से अधिक और रु. 150 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी की अधिकतम सीमा रु. 24 करोड़ होगी।
- iii. रु. 150 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी की अधिकतम सीमा रु. 32 करोड़ होगी।

क्र.सं.	अहं गतिविधियों/ क्रियाकलाप	मानदण्ड	प्रोत्साहन
i.	लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएसएलपी/ड्राई पोर्ट/एयर कार्गा/इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क)	पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी ए, बी, बी+ और सी) में ०५ एकड़ से अधिक और गैर-पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी-डी) के लिए १० एकड़ से अधिक भूमि पर निजी/पीपीपी/जेवी मोड के आधार पर लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए गए।	क(i) से क(v) में सूचीबद्ध सुविधाओं के अनुसार प्रोत्साहन।
ii.	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD)	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कम से कम १८ एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा।	क(i) से क(v) में सूचीबद्ध सुविधाओं के अनुसार प्रोत्साहन।

टिप्पणी: उपरोक्त सभी गतिविधियों/क्रियाकलापों के लिए पूंजीगत उपादान की अधिकतम मात्रा/सीमा क्रम संख्या— ५(क)(i), (ii), (iii) में अंकित परियोजना लागत के अनुरूप रहेगी।

ग. कौशल विकास प्रोत्साहन:

- i. रु. 25,000 का एकमुश्त समर्थन या प्रति व्यक्ति प्रशिक्षण की कास्तविक लागत, जो भी कम हो, संचालन की शुरुआत की तारीख से २ वर्ष की अवधि में अधिकतम १०० कर्मचारियों तक प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी। कौशल विकास प्रोत्साहन (नए लॉजिस्टिक्स प्रदाता के लिए- समान्य या विशेष) सहायता के लिए प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम १ माह से अधिकतम ३ माह होगी। कौशल विकास संस्थान को राष्ट्रीय कौशल विकास नियम (एनएसडीसी) / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / सरकार/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के तहत भाव्यता प्राप्त होना चाहिए।

टिप्पणी:

- i. ये प्रोत्साहन सभी नए और मौजूदा उद्योगों/लॉजिस्टिक इकाईयों, जिनका विस्तार हो रहा है, को अनुमत्य होंगे। राज्य सरकार नियमित रूप से इस नीति की प्रगति की समीक्षा करेगी और इसे और अधिक प्रभावी और परिणामनुमुखी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
- ii. टर्मिनल ऑपरेटरों को टर्मिनल के भीतर एक स्वच्छ वातावरण बनाए रखना होगा, जिसमें नियमित जांच की जाएगी और ऐसे टर्मिनल, जो योजना और स्वच्छ आवास पर्यावरण के अनुरूप होने में विफल रहते हैं, का रजिस्ट्रीकरण बंद कर दिया जाएगा।

6. प्राविद्य:

- एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, लिमिटेड लाइसिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी), ट्रस्ट, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और किसी भी अन्य कानूनी इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत संस्था/संस्थान इस नीति के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
- केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपकरणों अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) नोडल की परियोजनाओं को भी नीति में प्रदत्त सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की इकाइयाँ, जो किसी अन्य नीति के अधीन या केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं, ये इस नीति में उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन/लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ समेकित प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश, 2016 (समय-समय पर व्यासंशोधित) में विद्यमान औद्योगिक इकाई के पर्याप्त विस्तारीकरण की दी गयी परिभाषा के अनुरूप विद्यमान इकाई के नीजूदा पूँजी निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत या उससे अधिक का अतिरिक्त स्थिर पूँजी निवेश किया जाना आवश्यक होगा।
- उत्तराखण्ड माल और सेवा कर महानान संख्या (GSTIN) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत इकाई ही नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा करने के लिए पात्र होंगी।

7. योजनान्तर्गत पंजीकरण एवं वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने की प्रक्रिया:

*आवेदन पत्रों को नियमान्वय हेतु सम्बलीकृत उत्तराखण्ड उद्यम एकल नियमीकृत संसदीय एवं अनुक्रमन अधीनियम 2013 की भाग-10 के अन्तर्गत नियमीकृत सम्बलीकृत का अनुकार होंगी।

प्रथम चरण:

- उत्तराखण्ड एकल खिलौकी व्यवस्था (www.investinuttarakhand.uk.gov.in) के अन्तर्गत आवेदक द्वारा कौमन पंजीकरण फॉर्म (CAF) पर अपेक्षित अभिलेखों के साथ आवेदन।
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र तथा अपलोड अभिलेखों के आधार पर योजनान्तर्गत अहता की जांच के लिए अभिलेखों का सत्यापन।
- आवेदन पत्र तथा अभिलेखों के सम्परीक्षण पर सत्यापनकर्ता यदि कोई कमी पाता है, तो कमियों के निशाकरण के लिए सत्यापनकर्ता आवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।
- अहता की जांच के उपरान्त सम्बन्धित विभागीय नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र का अप्राप्तान।
- आवेदन पत्र की संवीक्षा/विश्लेषण के पश्चात एकल खिलौकी व्यवस्था के अन्तर्गत इकाई के पंजीकरण आवेदन पत्र को जिला/राज्य प्राधिकृत समिति के सम्मुख विचार/निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाना।
- जिला/राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदनोपरान्त निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति का प्रमाण पत्र ही नीति के अंतर्गत पंजीकरण भाना जायेगा।

द्वितीय चरण:

- अनुमोदित CAF ID से प्रोत्साहन/प्रतिषूर्ति दावे के लिए निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुप पर वांछित अभिलेखों के साथ आवेदन।
- महानिदेशक, उद्योग द्वारा नामित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया के अनुसार दावों का परीक्षण।

- iii. વિભાગ દ્વારા નામિત અધિકારી દ્વારા ઇકાઈ કા સ્થલીય નિરીક્ષણ।
- iv. વિભાગ દ્વારા નામિત અધિકારી કી અનુશાસન/નિરીક્ષણ રિપોર્ટ સહિત પ્રાથિકૃત અધિકારી દ્વારા દાવે કો રાજ્ય સ્તરીય સમિતિ કે સમુખ પ્રસ્તુત કિયે જાને હેતુ સમિતિ કે સદસ્ય સચિવ કો અગ્રસાધણ।
- v. સદસ્ય સચિવ દ્વારા આદેદન પત્ર કો વિચાર/નિર્ણય કે લિએ સમિતિ કે સમુખ પ્રસ્તુત કરના।
- vi. સમિતિ કે નિર્ણય કે ઉપરાન્ત આદેદન કો દાવે કી સ્વીકૃતિ/અસ્વીકૃતિ કી સૂચના કા પ્રેષણ।
- vii. સ્વીકૃત અનુદાન શાશી કા સંવિતરણ બજાટ ઉપલબ્ધતા કે અધાર પર કિયા જાયેગા।

8. વિત્તીય પ્રોત્સાહન દાવો કી સ્વીકૃતિ/સંવિતરણ કી પ્રક્રિયા એવં અપેક્ષિત અમિલેખ/પ્રમાણ પત્ર:

ક્ર.સ્ટ. પ્રોત્સાહન જારી ધરણ ચૈકલિસ્ટ માર્ડેલિટી (નિવેશક દ્વારા પ્રસ્તુત)

કરને કા ધરણ

- i. પ્રથમ કિશ્ટ ભૂમિ ક્રય કે સમય 10 પ્રતિશત કી પહલી કિશ્ટ | 1. કંપની નિગમન પ્રમાણપત્ર |
2. લૈણ સેલ ડીડ/લીજ ડીડ |
3. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટેન્ટ સે સ્વીકૃત ડીપીઆર |
4. વિત્ત કે સાધન |
- ii. દૂસરી કિશ્ટ લોઝિસ્ટિક્સ નીતિ કે 1. બિલ વાઉચર્સ, પ્રૂફ ઓફ પેમેન્ટ જાથી બૈલ સ્ટેટમેન્ટ પ્રોજેક્ટ પર કિયા ગયા ખર્ચ |
2. પ્રોજેક્ટ કે લિએ ચુકાયા ગયા માલ ઔર સેવા કર (જીએસટી) ચાલાન |
3. પરિયોજના સીલ કે ફોટો/દીદિયો સાદ્ય |
4. વાસ્તુકાર દ્વારા વિધિવત હસ્તાક્ષરિત પૂર્ણતા પ્રમાણ પત્ર (કાર્બસિલ ઓફ આર્કાટિક્યાર સે રિઝસ્ટ્રીક્યુટ એંડ રચિસ્ટ્રીકરણ પ્રમાણ પત્ર કે સાથી) |
- iii. તીસરી કિશ્ટ લોઝિસ્ટિક્સ નીતિ કે 1. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટેન્ટ પ્રમાણ પત્ર: પરિયોજના પર કિયા ગયા વાસ્તવિક વ્યય વિત્ત કે સાધન ઔર પરિયોજના લાગત કે 100 પ્રતિશત ઉપયોગ કો દર્શાતા હૈ |
2. ઇકાઈ દ્વારા પ્રવત્ત સેવાઓ/વ્યવસાયિક ગતિવિધિ પ્રારંભ કરને કા અપેન જીએસટીઆઈએન નમ્બર સે જારી પ્રથમ બીજાક કી પ્રતિ |
3. જિલા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર (ડીઆઈસી) દ્વારા જારી વાણિજ્યિક સંચાલન પ્રમાણપત્ર |
- iv. ચતુર્થ કિશ્ટ લોઝિસ્ટિક પાંલિસી કે 1. ઓફિસ બુક/વાર્ષિક વિત્તીય આખ્યા (રિપોર્ટ) (વાણિજ્યિક સંચાલન કે 2 વર્ષ પણ્યાત)

के 20 प्रतिशत की चौथी 2. प्रोत्साहन की चौथी और अंतिम किस्त जारी किस्त व्यवसायिक संचालन के 2 वर्ष बाद जारी की जाएगी। 2. प्रोत्साहन की चौथी और अंतिम किस्त जारी करने से पहले से स्वीकृत पदों के लिए प्रस्तावित/मूल्यांकित/वास्तविक लागत, जो भी कम हो, के आधार पर एक परियोजना लागत की पुनरायनना की जाएगी और तदनुसार फारी की जाएगी।

9. आवेदक की अर्हता पर निर्णय तथा नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति की प्रक्रिया:
 - i. वित्तीय प्रोत्साहन दावों की स्वीकृति के लिए निम्न समिति अधिकृत होगी:
 1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, एमएसएमई/औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन
 2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि
 3. राज्य स्तरीय बैंकर समिति के प्रतिनिधि
 4. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड
 - ii. अध्यक्ष महोदय को अनुमति से अन्य सदस्यों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है।
10. संवितरित प्रोत्साहन/समिक्षा की वसूली:
 - i. लाभार्थी इकाई द्वारा अपने आवेदन पत्र में किसी भी तरह की अनियमितता या तथ्यों को छुपाया गया हो, तो उद्योग निदेशालय द्वारा इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अपना प्रत्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। प्राप्त प्रत्यावेदन पर वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति के लिए गठित समिति का निर्णय अंतिम और वाध्यकारी होगा।
 - ii. यदि कोई इकाई भिन्ना साक्षात्/अभिलेखों के आधार पर लाभ प्राप्त करती है, तो उससे प्रदत्त प्रोत्साहन की घनराशि 18 प्रतिशत ब्याज/दण्ड ब्याज सहित राजस्व के सादृश्य वसूल की जा सकेगी।
11. नीति के क्रियान्वयन से सम्बन्धित आवेदन पत्रों के ग्राहक तथा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किये जाने के लिए महानिदेशक/आयुक्त उद्योग अधिकृत होंगे।

आज्ञा से,
विनय शंकर माण्डेय,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Articles 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.523/E-File-28344/VII-A-2/2023/02(4)2022/Dehradun, dated July 21, 2023 for general information.

Office memorandum:

July 21, 2023

No.523/E-File-28344/VII-A-2/2023/02(4)2022—The implementation of the Uttarakhand Logistics Policy, 2023, Promulgated for the purpose of providing support to the logistics sector in the State, in order of the Office Memorandum No 85/E-28344/VII-A-2/2023/02(4)2022, dated, January 31, 2023, of the Industrial Development Section 2, the Governor is pleased to allow to make the following guidelines/operational guidelines namely:-

**Guidelines for the implementation of Uttarakhand Logistics Policy-2023
Standard Operating Procedure**

To provide support to new and existing industries working in the field of logistics in the state, mainly to reduce logistics cost, strengthening of existing logistics infrastructure, generation of employment opportunities, raising the ranking of the state in logistics index and for the purpose of providing financial and non-financial Incentive assistance, Government of Uttarakhand, Industrial Development Section-2's office memorandum number 85/E-file-28344/ VII-A-2/2023/02(4)/2022, dated 31st January, 2023 has promulgated the Uttarakhand Logistics Policy-2023. The guidelines/standard operating procedure of the scheme for the implementation of this policy and the admissibility of the financial incentives provided in the policy are as follows:

1. Duration of the Guidelines:

These guidelines shall remain valid to the extent that the Uttarakhand Logistics Policy, 2023 remains in force or is amended by the state government.

2. Jurisdiction of the Guidelines:

The jurisdiction of these guidelines shall be in the entire Uttarakhand state.

3. Departments authorized to operate/implement the guidelines:

Micro, Small and Medium Enterprises Department/ Directorate of Industries, Uttarakhand shall be responsible for the implementation/operation of the guidelines.

4. Definition:

(I) In these policy, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

- a. Act means the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012.
- b. Authorized Committee means the District/State Authorized Committee constituted under Section, 3 of the Act.
- c. Authorized Officer means the designated officer at the level of Industries Department for the implementation of Uttarakhand Logistics Policy, 2023.
- d. State level committee means the committee set up to decide on the applications for financial incentives in Para, 9.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Uttarakhand logistics policy, 2023 shall have the meanings respectively assigned to the in that policy.

5. Financial Incentives:

a. **Capital subsidy for common logistics facilities:**

- For project cost up to Rs. 50 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 8 crore.
- For project cost above Rs. 50 crore and up to Rs. 150 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 24 crore.
- For project cost above Rs. 150 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 32 crore.

S.No.	Eligible Activities	Criteria	Incentive
I.	Warehousing facilities	Warehouse facility in 5,000 sq ft area with minimum investment of Rs 2.5 crore in hilly area (category A, B, B+ and C) and minimum 10,000 sq ft area with investment of Rs. 5 crore for non-hilly area (Category-D).	20% of the project cost
II.	truck terminal	Truck terminal set up with an investment of Rs. 5 crore and a minimum area of 45,000 sq.ft.	20% of the project cost
III.	Transport / Truck Owner / Fleet Operator / Aggregator	Purchase of minimum 3 trucks/small trucks/mini pickup trucks/reefer vans (ex-showroom price).	10 percent on large and 15 percent on small and medium trucks, maximum Rs. 10 lakh
IV.	Cold Storage	Minimum area of 5,000 sq.ft.	15 percent of the project cost shall be given in addition to the subsidy provided by the Central Government for cold storage.
V.	Basic Facilities	Developed infrastructure in the form of internal transport system, power lines, communication facilities, water distribution and water augmentation facilities, sewage and drainage lines, waste treatment and disposal facilities, fire tender arrangements, parking, weighing bridge, medical centre.	20% of the project cost

Note: The maximum quantity/limit of capital component for all the above activities shall be subject to the project cost mentioned in serial number-5(a)(i), (ii), (iii).

b. **Capital Subsidy for Specialized Logistics Units**

- For project cost up to Rs. 50 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 8 crore.
- For project cost above Rs. 50 crore and up to Rs. 150 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 24 crore.

iii. For project cost above Rs. 150 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 32 crore.

S.No.	Eligible Activities	Criteria	Incentive
I.	Logistics Park (MMLP/Dry Port/Air Cargo/Integrated Logistics Park)	Logistics Parks developed on private/PPP/JV mode basis on land more than 05 acres in hilly area (Category A, B, B+ & C) and more than 10 acres for non-hilly area (Category-D).	Incentives as per facilities listed in a(i) to a(v)
II.	Inland Container Depot (ICD)	The Inland Container Depot will be built over an area of at least 18 acres.	Incentives as per facilities listed in a(i) to a(v)

Note: The maximum quantity/limit of capital component for all the above activities shall be subject to the project cost mentioned in serial number-5(a)(i), (ii), (iii).

c. Skill Development Promotion:

i. One time support of Rs. 25,000 or the actual cost of training per person, whichever is less, shall be given as incentive up to a maximum of 100 employees over a period of 2 years from the date of commencement of operations. Skill development incentives (for new logistics provider – general or specific) The duration of training for assistance shall be minimum 1 month to maximum 3 months. The skill development institute should be recognized by National Skill Development Corporation (NSDC)/ University Grants Commission (UGC)/ Govt./ All India Council for Technical Education (AICTE).

Note:

i. These incentives shall be admissible to all new and existing industries/logistics units which are undergoing expansion. The State Government shall regularly review the progress of this policy and take necessary steps to make it more effective and result oriented.

ii. Terminal operators shall maintain a hygienic environment within the terminal, which shall be subject to regular inspection and the registration of terminals which fail to conform to the hygienic food and accommodation environment shall be de-registered.

6. Eligibility:

(i) Sole Proprietorship, Partnership Firm, Cooperative Society, Company, Limited Liability Partnership (LLP), Trust, Non-Governmental Organization (NGO) and institute/institutions registered as any other legal entity can avail financial incentives under this policy.

(ii) Public Undertakings of the Central or State Government or the projects of Public Private Partnership (PPP) model shall also be allowed to take advantage of the facilities provided in the policy.

(iii) Units in the logistics sector who receive financial incentives under any other policy or from any other department of the Central/State Government will not be eligible to receive the financial incentives/benefits mentioned in this policy, because a provision for integrated incentive has been made here.

(iv) According to the definition of adequate expansion of the existing industrial unit in the State's Micro, Small and Medium Enterprises Implementation Order, 2015 (as amended from time to time), additional fixed capital investment of minimum 25

percent or more in the existing capital investment of the existing unit shall be necessary.

(v) Only units registered under Uttarakhand Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) shall be eligible to claim the incentive assistance provided in the policy.

7. Process of getting registration and financial incentives under the scheme:

**The time limit for disposal of applications will be according to the time limit prescribed under Section-10 of the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012.*

Phase I:

- i. Under the Uttarakhand single window system (www.investuttarakhand.uk.gov.in), application by the applicant on the common application form along with the required documents.
- ii. Verification of records for verification of eligibility under the scheme on the basis of application form and uploaded records by the authorized officer.
- iii. If the verifier finds any deficiency on scrutiny of the application form and records, then the authorized officer can obtain clarification from the applicant for the removal of deficiencies.
- iv. Forwarding of application to concerned departmental nodal officer after checking eligibility.
- v. After scrutiny/analysis of the application, the unit's registration application shall be presented before the district/state authorized committee for consideration/decision under the single window system.
- vi. Issue of registration under the scheme by the authorized officer after the approval of the district/state authorized committee.

Phase II:

- i. Application on prescribed application form for claiming incentive/reimbursement from approved CAF ID along with required documents.
- ii. Examination of claims as per standard operating procedure by an authorized officer designated by the Director General of Industries
- iii. Site inspection of the unit by officer designated by the department.
- iv. Along with the recommendation/inspection report of the officer nominated/authorized by the department forwarding of the claim by the authorized officer to the member secretary of the committee for being presented before the committee.
- v. Submission of the application by the Member-Secretary before the Committee for consideration/decision.
- vi. Dispatch of information of acceptance/rejection of claim to the applicant after the decision of the committee.
- vii. The disbursement of the sanctioned grant amount shall be done on the basis of budget availability.

8. Process of acceptance/disbursement of financial incentive claims and required records/certificates:

Sl.no	Phase of Incentive Release	Stages	Checklist Modality(Submission by Investor)
i.	1 st Instalment	The 1 st instalment of 10% at the time of Land Purchase	1. Company Incorporation Certificate 2. Land Sale Deed/ Lease Deed 3. Approved DPR from Chartered Accountant 4. Means of Finance
ii.	2 nd Instalment:	The 2 nd instalment of 35% of the total Incentive under the Logistic Policy shall be released after ensuring that 90% of the project cost has been utilized on the project.	1. Bill Vouchers, Proof of Payments and Bank Statement: Expenditure incurred on the project 2. GST challan paid for project 3. Photo/Video evidence of Project site 4. Completion Certificate by duly signed by Architect (registered with Council of Architecture having a valid registration certificate)
iii.	3 rd Instalment:	The 3 rd instalment of 35% of the total Incentive under the Logistic Policy shall be released only after confirming the commencement of commercial production through physical verification by the District Industries Centre / Directorate of Industries and issue of Consolidated consent & authorization (CCA) from the Pollution Control Board	1. Chartered Accountant Certificate- Actual expenditure incurred on the project showing the means of finances and 100% utilization of Project Cost 2. Copy of the first invoice issued by the entity from its GSTIN number for the services provided/commencement of business activity. 3. Commercial Operation Certificate issued by DIC
iv	4 th Instalment:	The 4 th instalment of 20% of the total Incentive under the Logistic Policy shall be released only after 2 years of commercial operation	1. Audit book/ Annual Financial Reports (after 2 years of Commercial Operation) 2. Before releasing of 4 th & final instalment of Incentive a project cost shall be recalculated based on the proposed/ appraised / actual cost, whichever is less, for the already approved items and released accordingly

9. Decision on the eligibility of the applicant and the process of approval of the financial incentives provided in the policy:

i. The following committee shall be authorized to approve the financial incentive claims:

1. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary - Chairperson Secretary, MSME/ Industrial Development, Govt. Of Uttarakhand
2. Principal Secretary/ Secretary, Finance or their nominated - Member

representative

3. Representative of State Level Bankers Committee	-	Member
4. Director General/Commissioner, Industries, uttarakhand	-	Member Secretary

H. With the permission of the Chairman, other members can be invited as per the requirement.

10. Recovery of incentive/subsidy disbursed:

- I. In case of any irregularity or suppression of facts by the beneficiary unit in its application form, Directorate of Industries may issue a show cause notice to the unit and allow it to submit its representation/reply within 15 days. The decision of the committee constituted for approval of financial incentives on the representation received shall be final and binding.
- II. If any unit obtains benefits on the basis of false evidence/records, then the amount of incentive given from it can be recovered as per the revenue along with 18 percent interest/penal interest.

11. The Director General/Commissioner Industries is authorized to develop online portal, and formats of applications related to the implementation of the policy.

By Order

VINAY SHANKAR PANDEY
Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुक्षकी, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2023 ई० (प्रावण 21, 1945 शक सम्वत)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विभिन्नां, आकारं, विभिन्निया इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 235/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023, Shri Anoop Singh Bhakuni is posted as 4th Additional Civil Judge (Jr. Div.) Haridwar in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 236/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May 2023, Ms. Hina Kousar is posted as 4th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun in the vacant Court

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 237/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023, Ms. Shristi Shukla is posted as Judicial Magistrate-II Dehradun in the vacant Court

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 238/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023, Ms. Radha Kusshreshtha is posted as Judge & Magistrate Tanakpur, District Champawat in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 239/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023, Ms. Nancy Chhabra is posted as 5th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 240/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023, Ms. Shafali Chandravanshi is posted as Judicial Magistrate- II, Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 241/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023, Ms. Sonam Rawat is posted as Judicial Magistrate-IV Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 242/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023, Shri Abhishek Kumar Mishra is posted as Additional Civil Judge (Jr. Div.) Rishikesh, District Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 243/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May, 2023, Shri Jatin Mittal is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 244/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May 2023 Shri Naveen Rana is posted as Civ I Judge (Jr Div), Gangolihat, District Pithoragarh in the vacant Court

Note: Ms. Avantika Singh Chaudhary, Civil Judge (Jr Div), Dildihat, District Pithoragarh shall continue hold Camp Court at Gangolihat, District Pithoragarh as per provisions of Notification No.208/UHC/Admin.A-2/2023 dated 25.04.2023 of the Court, until Shri Naveen Rana completes his Foundation Training.

NOTIFICATION

May 25, 2023

No. 245/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No 320/XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25th May 2023, Ms. Tanya Madhavi is posted as Judicial Magistrate, Pithoragarh in the vacant Court.

All above orders shall come into force with immediate effect.

By Order of the Court

Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL

Registrar General

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALNOTIFICATION

June 07 2023

No. 256/XIV-a-39/Admin.A/2016--Ms. Kapana, 1st Additional Civil Judge (Jr Div) Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 15 days w.e.f. 26.04.2023 to 10.05.2023.

NOTIFICATION

June 07 2023

No. 257/XIV/a-19/Admin.A/2009--Ms. Jayot Bala, Civil Judge (Sr Div) Haldwani District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 15.05.2023 to 24.06.2023 with permission to prefix 13.05.2023 & 14.06.2023 as second Saturday and Sunday no. days respectively.

NOTIFICATION

June 07 2023

No. 258/XIV/a-33/Admin.A/2021--Ms. Prayanshi Nagarkoti, 2nd Additional Civ I Judge (Jr Div), Rudrapur District Udhampur Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 01.05.2023 to 14.05.2023.

NOTIFICATION

June 07 2023

No. 259/XIV-a-38/Admin.A/2020--Ms. Shubhangi Gupta Civil Judge (Jr. Div.), Amora is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 20.02.2023 to 06.03.2023.

NOTIFICATION

June 08, 2023

No. 260/XIV-28/Admin.A/2008--Shri. Sudhir Tomar Judge, Family Court-II Rudrapur, District Udhampur is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 08.05.2023 to 20.05.2023 with permission to prefix 07.05.2023 and suffix 21.05.2023 as Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITALNOTIFICATION

June 13, 2023

No. 264/UHC/Admin.A-2/2023--In supersession of earlier Notification No. 208/JHC/Admin.A-2/2023 dated 25.04.2023, Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragarh is directed to hold Camp Court at Gangolihat, District Pithoragarh for a week in every month until Shri. Naveen Rana Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat, District Pithoragarh resumes his duties after completion of foundation training or till further orders whichever is earlier.

By Order of the Court

Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL

Registrar General

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALNOTIFICATION

June 14, 2023

No. 265/UHC/Admin.A/2023--

"Standard Operating Procedure for the Investigation Section of the Vigilance Cell, High Court of Uttarakhand"

The High Court of Uttarakhand Vigilance Rules, 2019, as amended vide Notification No. 250/UHC/Admin.A/2023 Dated 06 June, 2023 (As approved by the Government of Uttarakhand vide letter no. 173/XXXVI-A 1/2023-345/2019 Nyay Anubhag-1 Dehradun Dated 24.05.2023), provides for the establishment of an Investigation Section in the Vigilance Cell.

Composition of the Investigation Section of the Vigilance Cell, as provided in Rule 6, is as under:

1. One Vigilance Officer (of SSP/SP level, on deputation from police department, having minimum 8 years of service, preferably with experience in Vigilance/anti-corruption work/CID)

2. Two Inspectors of Police having minimum 15 years of service, preferably with experience in Vigilance/anti-corruption work/CID. One may have considerable service in Garhwal Region and another in Kumaon Region.

3. One Head Constable having minimum 10 years of service.

4. Three Constables with minimum 5 years of service.

With regard to the working of Investigation Section of the Vigilance Cell, following Standard Operating Procedure is being laid down. The Police Personnel working in the Investigation Section, shall scrupulously follow the Standard Operating Procedure

- (A) Subject to written orders issued by Hon'ble the Chief Justice generally or in a specific case, the Police Personnel deputed in the Investigation Section shall work within the scope as provided under this SOP.
- (B) Subject to general supervision of Hon'ble the Chief Justice, the Investigation Section shall work under the direct control of Registrar Vigilance, High Court of Uttarakhand.
- (C) Investigation Section shall carry-out its activities only on the directions issued by the Registrar Vigilance, which shall be issued in writing.
- (D) If in any specific case, it would not be feasible to issue written directions forthwith, directions issued shall be reduced into writing at the earliest and shall be brought to the notice of Hon'ble the Chief Justice.
- (E) On the requisition of the Investigation Section of the Vigilance Cell, all communication/correspondence with any Judicial Officer of the State Judiciary in relation with any matter with the Vigilance Cell, shall be made by the Registrar Vigilance.
- (F) Police Personnel deputed in the Investigation Section shall not make any direct communication/correspondence to any Judicial Officer.
- (G) On the requisition of the Investigation Section of the Vigilance Cell, all communication/correspondence with the District Judges in relation to any matter with the Vigilance Cell, to seek any information/document relating to an officer, shall be made by the Registrar Vigilance.
- (H) Police Personnel deputed in the Investigation Section can make direct communication/correspondence with regard to any matter pending with the Vigilance Cell with other departments/offices, after bringing it to the notice of the Registrar Vigilance.
- (I) In course of any Vigilance matter, statement of any Judicial Officer if required, shall be recorded in presence of the Registrar Vigilance.

By Orders of Hon'ble Court,
Sd/-
ANUJ KUMAR SANGAL,
Registrar General

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून

आदेश

28 जून, 2023 ई०

सच्चा—एसपीटी—आर (गति सीमा) /2023—केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—112 की उपधारा (2) में प्राधिकारिता है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस नियमित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा—116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर सलान है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011(यथा संशोधित) के नियम—180 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने—अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर नियन्त्रण या सामान्यतया मोटर यानों या किसी विशिष्ट वर्ग या घरों के मोटर यानों के प्रयोग पर नियन्त्रण या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहाँ वे लागू होते हैं, सूधना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में पुलिस, परिवहन एवं लोक नियन्त्रण विभाग के अधिकारियों की समिति द्वारा जनपद के विभिन्न मार्गों पर गति सीमा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः समिति द्वारा दिये गये प्रस्ताव के क्रम में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—112 की उपधारा(2) के साथ परित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011(यथा संशोधित) के नियम—180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देहरादून जनपद होकर निकलने/चलने याते नगरीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र/क्षेत्रों के मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रीनिवार द्वाहनों की गति सीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है :—

क्र० सं०	मार्ग का नाम	वाहन का प्रकार			
		त्रिपहिया वाहन की अधिकतम गति सीमा	द्विपहिया वाहन की अधिकतम गति सीमा	ठल्का चार पहिया वाहन की अधिकतम गति सीमा	मध्यम/भारी वाहन की अधिकतम गति सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	घण्टाघर से आरटीओ- डायवर्जन	30	30	30	20
2	डायवर्जन से मालसी-कुडालगेट-शहंशाही- राजपुर	25	30	30	20
3.	डायवर्जन से राजपुर	30	30	30	20
4.	सहस्रधारा क्रॉसिंग से राजपुर रोड मसूरी बाईपास	30	30	30	20
5	सर्व चौक से रायपुर	30	30	30	20
6.	वेनी बाजार, ई०सी० रोड-आराघर-धर्मपुर रिस्पना-जोगीवाला	30	30	30	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	सिंधनम से हरिद्वार बाईपास-आईएसबीटी	20	30	30	20
8.	आई०एस०बी०टी० से द्रोसपोर्ट नगर	30	30	30	20
9.	आई०एस०बी०टी० से शिमला बाईपास चौक	30	30	30	20
10.	आराधर से ग्रिस चौक	30	30	30	20
11.	ग्रिस चौक से सहारपुर चौक-पटेलनगर-शिमला बाईपास	30	30	30	20
12.	शिमला बाईपास चौक से खाटकाली	30	40	60	30
13.	घटाधर से चकराता रोड-बिन्दाल-बल्लपुर-प्रेमनगर	30	30	30	20
14.	प्रेमनगर से सुखोवाला	25	40	60	30
15.	धर्मपुर चौक से मालामार्विर बाईपास चौक	30	30	30	20
16.	रेस्ट कैम्प से बन्नू रुकुल से अपवाल चैकरी	30	30	30	20
17.	जोगीवाला चौक से ग्रिं रोड लाडपुर	30	30	30	20
18.	बल्लपुर चौक से जी०एन०एस० रोड-कमला पैलेस-सेट ज्यूड-द्रोसपोर्ट नगर	30	30	30	20
19.	आई०एस०बी०टी० से शिमला बाईपास-धर्मवाला-पैंटर मार्ग	25	30	30	20
20.	ग्रेट वैल्यू से केनाल रोड सहस्रधारा बाईपास	30	30	30	20
21.	नेहरू कॉलोनी से ०६ नंबर पुलिया, किंदवाला, रायपुर	30	30	30	20
22.	रेसकोस चौक से पुलेस खाइन, धर्मपुर	30	30	30	20
23.	बसंत विहार-सीमाधार	30	30	30	20
24.	मोहकमपुर से लाल तप्पड	30	60	60	60
25.	लाल तप्पड फनवैली से पुलिस चौकी तक	30	40	60	40
26.	लाल तप्पड से आगे छिद्रवाला तक	30	60	60	60
27.	छिद्रवाला बाजार	30	40	60	40
28.	छिद्रवाला से नेपालीकार्म-रायवाला	30	60	60	60
29.	रायवाला बाजार	30	40	60	40
30.	भानियावाला से जौलीप्रान्ट, रानीपोखरी-डांडी तक	30	40	60	40
31.	रायपुर से मालदेवता	20	30	30	20
32.	कारगी चौक से इन्द्रेश हास्पिटल लाल मुल	30	30	30	20
33.	श्यामपुर से कोयलधाटी तिराडा	25	40	60	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34.	नटराज से श्यामपुर तिराहा	25	40	40	30
35.	कोयलघाटी से आईटीपीएल एम्स हॉस्पिटल	25	40	40	30
36.	कोयलघाटी से भुनी की रेती	25	30	40	20
37.	नटराज से भद्रकाली-खाचा घोस्त लालगढ़ीला तिराहा	28	30	30	20
38.	दिलासाम से हाथीबख्तकला-अनारवाला-शुच्छूपा नी-जोहड़ी-गुनियालगांव-मालसी	20	30	30	20
39.	सनपाक घोराहा से आईटीवीपी सीमावार	20	25	30	20
40.	कोवली रोड से पॉडिटवाली	20	25	30	20
41.	रिस्पना से एमडीडीए- समिवालय कोलोनी-दून शिवविद्यालय-मोर्योवाला	20	25	30	20
42.	टन्नर रोड एवं सुमाष रोड	20	25	30	20
43.	सहारनपुर रोड से अन्दबनी-घोरला	20	25	30	20
44.	मियावाला चौक से बालावाला-शुलरघाटी	20	25	30	20
45.	मियावाला से तुनवाला-रायपुर	20	30	30	20
46.	रायपुर-नथुवालाला	20	30	30	20
47.	ऋषिकेश नटराज चौक से त्रिवेणीघाट नीराहा	20	30	30	20
48.	धैराघर से प्रिंस चौक	20	30	30	20
49.	किशननगर चौक से कोलागढ़	20	30	30	20
50.	बल्लपुर चौक से गढ़ीकेन्ट धाना	25	40	40	20
51.	नालापानी से आमदाला	20	30	30	20
52.	आईटी पार्क से ननुरखेड़ा-आमदाला रायपुर रोड	20	30	30	20
53.	कुदालगढ़ से भसूरी	30	30	40	30
54.	सुद्धोवाला से विकासनगर	30	40	50	30
55.	विकासनगर से कालसी	30	30	40	30
56.	भोगपुर से इठारना	25	30	40	20
57.	रानीपोखरी से भोगपुर	25	40	40	30
58.	डंडी से नजटराज चौक	25	40	40	30
59.	सात मोड़ क्षेत्र	20	25	30	20
60.	नंदा की चौकी से पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी बिधोली	25	40	40	30
61.	शिमला बाईपास से सेलाकुर्झ	30	30	40	30
62.	हरबटपुर से धर्मावाला-दररिट	30	30	40	30
63.	हरबटपुर से वुल्हाल वाया ढकसनी	30	30	40	30

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
६४.	एसडीआरएफ तिराहा भानियावाला से थानो	२०	२५	३०	२०
६५.	हरिवाला से नेपालीकाम	३०	८०	८०	६०
६६.	नेपालीकाम से सरयवाला	३०	६०	८०	६०
६७.	रायपुर से थानो-भोगपुर	२५	४०	४०	३०
६८.	कुलहाल-डाकपत्थर-बाड़धाला	२०	२५	३०	२०
६९.	बरोटीयाला-विकासनगर	२५	४०	४०	२०
७०.	बरोटीयाला-अम्बाड़ी	२५	४०	४०	३०
७१.	बाईपास-मोधरोवाला-दूधली-डॉइवाला	२५	४०	४०	२०
७२.	सेलाकुई-भाउवाला	२५	४०	४०	२०
७३.	सुद्दोवाला-भाउवाला	२५	४०	४०	३०
७४.	भानियावाला से डॉइवाला	२५	४०	४०	—

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रातिबन्ध निम्नलिखित शास्त्रों के अंदीन प्रभावी होगा :

(१) मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा-११६ में विनिर्दिष्ट साईन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों ओर-प्रारम्भिक एवं अतिम पिन्डु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह भर आई०आर०सी० कोड के मानक ये अनुसार संबंधित सरक के स्थानित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि घासन घालकों वाले इसकी जानकारी ये ज्ञान हो सके तथा ये रात्रि में भी अमले इसके लिए रिहो-रिफ्लेक्टर टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(२) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, १९८९ के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा —

- (अ) अग्निशमन वाहन।
- (ब) एम्बुलेंस।
- (स) पुलिस वाहन।
- (द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्थ सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।
- (य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।

(३) उपरोक्त सालिका के क्रमांक-२ में उल्लिखित मार्गों/स्थानों को छोड़कर जनपद के अन्य नगरीय क्षेत्रों के मार्गों में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा-११२ की उपधारा-(१) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-१३७७ दिनांक ०८-०४-२०१८, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

८० (अस्पष्ट)

पुलिस उप महानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद देहरादून

आदेश

25 जुलाई, 2023 ई०

सख्ता एकाधीक्षी आर-08(ई रिक्षा)/2023—एवं वृद्धांश सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत विकासनगर की यातायात व्यवस्था, दुर्घटना नियन्त्रण एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत विकासनगर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर अनियमित एवं अनियन्त्रित रूप से सचालित हैं रिक्षा वाहनों का संचालन सीमित किये जाने के सम्बन्ध में तकनीकी एवं वैज्ञानिक अध्ययन हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात क्षेत्राधिकारी यातायात एवं क्षेत्राधिकारी विकासनगर जनपद देहरादून की एक समिति गठित की गयी थी समिति हारा परीक्षणोपरान्त यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत विकासनगर हेतु आन्तर्गत संचालित हैं—रिक्षा वाहनों का संचालन निम्न मार्गों पर प्रतिबन्धित किये जाने की संस्तुति की गयी है—

1. हर्दरटपुर चौक से चौकी बाजार—अम्बाई पंचायत मार्केट—कालसी बाजार तक।
2. डाकपत्थर तिराहा—डाकपत्थर बैराज तक।

उस के अतिरिक्त निम्न मार्गों पर ई-रिक्षा वाहनों का संचालन किया जा सकता है—

1. बरोटीबाला / अम्बाई मोटर मार्ग।
2. कैनाल रोड।
3. हरिपुर तिराहा हर्दरटपुर से ढकरानी।
4. बेदांश स्वीट शॉप बाबूगढ़ से बरोटीबाला तक।

गठित समिति हारा संयुक्त हस्ताक्षरित आकड़ा के आलोक में जनपद देहरादून अन्तर्गत विकासनगर के अति-व्यस्ततम स्थान हर्दरटपुर चौक से चौकी बाजार—अम्बाई पंचायत मार्केट—कालसी बाजार तक तथा डाकपत्थर तिराहा—डाकपत्थर बैराज तक वी यातायात व्यवस्था के कुशल संचालन के दृष्टिगत उक्त मार्गों पर संचालित हैं—रिक्षा वाहनों को प्राचीमिक तौर पर प्रतिबन्धित किये जाने से उक्त मार्गों में यातायात का दबाव कम हुआ है इस प्रकार उपरोक्त मार्गों पर पूर्व से संचालित विक्रम वाहनों के साथ—साथ है—रिक्षा वाहनों का संचालन होने से विकासनगर क्षेत्र में डैपन यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित किये जाने तथा है—रिक्षा वाहनों के संचालन को उक्त मार्गों पर प्रतिबन्धित किये जाने के उद्देश्य से परीक्षणोपरान्त एवं शन्यक लियारोपरान्त पूर्णत प्रतिबन्धित किया जाना खारेजनिक परिकल्पना सुविधा के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में उक्त मिशन लिया जाना जनहित में आवश्यक हो गया है।

अत मैं दलीप सिंह कुवर, पुलिस उपमहानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून उत्तराखण्ड बोर्डरयान निधमाधारी, 2011 के नियम-180 के उपनियम-1 से प्रदत्त अधिकारों के तहत प्रश्नगत मार्गों वथा हर्दरटपुर चौक से चौकी बाजार—अम्बाई पंचायत मार्केट—कालसी बाजार तथा डाकपत्थर तिराहा—डाकपत्थर बैराज पर संचालित है—रिक्षा वाहनों का संचालन समय प्रति 8.00 अड्डे से रात्रि 8.00 बजे तक पूरीत प्रतिबन्धित किये जाने के उद्देश निर्गत करता हूँ।

उपरोक्त प्रतिबन्धित आदेश का विधिवत अधिसूचना, गजट नोटिफिकेशन होने एवं सम्बन्धित स्थान मार्गों पर तदनुसार सूचना पह पर प्रदर्शित किये जाने की सिधि से प्रभावी होगा।

दलीप सिंह कुवर,
पुलिस उपमहानिरीक्षक /
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन,
उधमसिंह नगर

अधिसूचना

16 जुलाई, 2023 ई०

पत्रांक ९२४७ / गति सीमा निर्धारण / २०२३-केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा-११२ की उपधारा-(२) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या मुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा-११६ के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात यिन्ह रखेकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न हैं या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियनायली, २०११ (यथा संशोधित) के नियम-१८० में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य दोनों में संजिरद्वीकर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निवन्धन या सामान्यत मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटरयानों के प्रयोग पर निवन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या भाग पर या उसके निकट, जहाँ ये लागू होते हैं, सूचना पटटों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे।

अतः मोटरयान अधिनियम १९८८ की धारा-११२ की उपधारा-(२) के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमायली, २०११ (यथा संशोधित) के नियम-१८० में प्रदत्त शवित्रियों का प्रयोग करते हुए उधमसिंह नगर जनपद से होकर निकलने/चलने वाले वाले ऐसे मार्गों या मार्गों के अंश पर, जो नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत की अधिकारिता से बाहर हो, संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गतिसीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है:-

Details of motor road in the dist. Udhampur Nagar under CD, PWD, Khatima

SL NO	DIVISION	CATEGORY OF ROAD	NAME OF ROAD	TOTAL LENGTH OF THE ROAD IN KM.	CHAINAGE (UNDER JURISDICTION OF DIVISION)	Category of vehicles and speed limit(km/hour)			
						HEAVY GOODS VEHICLE /HEAVY PASSANG ER VEHICLE / MEDIUM GOODS VEHICLE/ MEDIUM PASSANG ER VEHICLE	LIGHT GOODS VEHICLE /LIGHT PASSANG ER VEHICLE	TWO WHEEL ER	THREE WHEEL ER
FROM	TO								

National Highways (NH)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CD khatima	NH 731-K	Khatima to majholi Piplihi highway	13.200	0.000	13.200	60	70	60	40

State Highways (SH)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CD khatima	SH-41	Ranmagar kotadhungi Holdwan Kathgodam Chorgaliya Sitaranji Buzi state highway	23.100	95.600	(19.000)	60	70	60	40
2	CD khatima	SH-107K	Khatma Melegarh Gumrahiya state highway	10.600	0.000	10.600	50	60	50	40
3	CD khatima	SH-70	Jhankalya birlia sripur bishnuwa bigrabagh chakarpur julapur Jhankalya modi sarakhamji manaksagar state highway Jhankat birlia shreepur bishnuwa bigrabagh chakarpur falkotli road	58.200	0.000	54.200	50	60	50	40

4	CD khelma	SH 46	Parmpur mudhavada state highway	14,000	0,000	14,000	40	30	50	40
---	--------------	-------	---------------------------------------	--------	-------	--------	----	----	----	----

Major Distt Road (MDR)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CD khelma	MDR	Sankheda sankheda nali motor road	17,600	0,000	17,600	50	60	50	40
2	CD khelma	MDR	Km 12 of NH 123 to nandwana gundwara, salob baoli salob lepeda hozar nankantin (Buri) ransoli motor road	16,550	0,000	16,550	50	60	50	40
3	CD khelma	MDR	Sirsa road to shahidpur nandwana jalcamp sadeo motor road	22,010	0,000	22,010	60	70	60	40
4	CD khelma	MDR	Portion of albergi market of PK road nokhla chitliyara thamli thor motor road	13,950	0,000	13,950	50	60	50	40

Other Distt Road (ODR)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CD khelma	ODR	Tedaghai chendoll puranpur pachpeda gandhinagar bauni saldamli Jhankai motor road margin	12,500	0,000	12,500	40	50	50	40
2	CD khelma	ODR	Khempur matecha to bijli road	9,800	0,000	9,800	40	50	50	40
3	CD khelma	ODR	Khelma chitli birliya Jhankai road	7,650	0,000	4,650	30	60	50	40
4	CD khelma	ODR	Paheniya shripur bichunwa road	11,000	0,000	11,000	30	60	50	40
5	CD khelma	ODR	Hamapur, shuklagram pedagao donibhanagar motor road	13,850	0,000	13,850	50	60	50	40
6	CD khelma	ODR	Khelma manghat road	0,900	10,600	11,500	60	70	60	40

Details of motor road in the dist. Udhampur under PD, PWD, Rudrapur

S. L. N. O.	DIVISION	CATEGORY OF ROAD	NAME OF ROAD	TOTAL LENGTH OF THE ROAD IN KM	CITATION (UNDER JURISDICTION OF DIVISION)	Category of vehicles and speed limit (km/hours)				
						HEAVY GOODS VEHICLE	HEAVY PASSENGER VEHICLE/ MEDIUM GOODS VEHICLE/ MEDIUM PASSENGER VEHICLE	LIGHT GOODS VEHICLE	LIGHT PASSENGER VEHICLE	TWO WHEELER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					FROM	TO				

State Highways (SH)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PD, PWD - Rudrapur	SH-3	Gadarpur-dineshpur malkotia jodhpur road	40.900	0.000	26.900	50	60	50	40
2	PD, PWD - Rudrapur	SH-61	Sardar nager buriya deulat bannkhira road	71.400	0.000	9.000	50	60	50	40
3	PD, PWD - Rudrapur	SH-44	Nagh kichhi road	20.725	0.000	20.725	60	70	60	50
		Total		132.025	0.000	36.625				

Major Distt. Road (MDR)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PD, PWD - Rudrapur	MDR	Kichhi-damir road	8.885	0.000	8.885	50	60	50	40
2	PD, PWD - Rudrapur	MDR	Jafarpur-gujarhing road	10.000	0.000	10.000	50	60	50	40
		Total		18.885		18.885				

Other Distt Road (ODR)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Gidupuri vizinagola road	3,600	0,000	3,600	40	50	40	30
2	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Rudrapur bypass road	2,700	0,000	2,700	40	50	40	30
3	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Bolramnagar link road	0.120	0,000	0.120	40	50	40	30
4	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Azad nager sunera bawars lelpur road	7,000	0,000	7,000	40	50	40	30
5	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Bhuraoni chattarpur mukkola road	7,000	0,000	7,000	40	50	40	30
6	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Shimla plateau kunals road	8,960	0,000	8,960	40	50	40	30
7	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Nagla Talpur road	9,636	0,000	9,636	50	60	60	40
8	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Gadherpur mukk khanna road	8,000	0,000	8,000	50	60	60	40
9	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Gadherpur Balramnagar enthaligunj road	9,615	0,000	9,615	40	60	60	40
10	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Maxabhar baejee siddhiganj crossing link road	10,700	0,000	10,700	40	50	40	30
11	PD, PWD -Rudrapur	ODR	Foria pipliya med to suryaengar dorn dain tillyojpur basgar road	14,650	0,000	14,650	40	50	40	30
			TOTAL	82,051		82,051				

ANPR LOCATION

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PD-PWD- NH DIVISION HALDWANI	NH 74/SH 37	From puhalimata bridge to UP border (ANPR) Integrated CP station	2.25	229.300 NH-74	57.50 SH-37	*	*	*	*
2	NH 41-D/V rudrapur	NH 87	From rudrapur to kuhgedam (ANPR) Integrated CP rudrapur	49.780	43.446	93.226	60	80	60	40

* राष्ट्रीय मार्ग छण्डलोक निर्गण यिभाग द्वारा अधिगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के किमी० 239.20 से राज्य मार्ग संख्या-37 के किमी० 57.50 तक पुलभद्दा से उत्तर प्रवेश बोर्डर तक 4 लेन का पार्थ गतिसार है। उक्त के दृष्टिगत धार्हन हल्का/भारी गति सीमा गही वर्षायी जा सकती अन्यथा दुर्घटना की संभावना बही रहेगी। उक्त कार्य की समाप्ति की सम्भावित तिथि 30 अक्टूबर 2023 अधिगत करायी गई है, अतः उक्त के पश्चात ही गति सीमा का निर्धारण किया जाना उचित होगा।

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा:-

- गोटरथान अधिनियम, 1988 की धारा-110 में शिनिर्दिष्ट धारा और प्रतिबन्धित स्थान के बोर्ड-छोर-प्रारम्भिक एवं अंतिगत गिन्तु पर तथा गद्य में गी जागृ-जागृ पर आईआरआरसी० फोर्म के मानक गी अनुसार राष्ट्रियता राजक के रूपान्तर यासे यिभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा जिस गाउन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके। राज्य में उक्त साइन बोर्ड प्रवर्तित हो इसके लिए रिट्रो-रिपलेशिट टेक का प्रयोग किया जायेगा।
- उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय गोटरथान नियमावली, 1980 के यिनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के बाह्नों पर लागू नहीं होगा।
 - (अ) अनिशामन धार्हन।
 - (ब) एम्बुलेंस।
 - (स) पुलिस धार्हन।
 - (द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य वल तथा अर्ध सैन्य वल के लिए प्रयुक्त होने वाले धार्हन।
 - (य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त धार्हन।
- उपरोक्त तालिका के कॉलम-4 पर उल्लिखित मार्गों/स्थानों एवं जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्र के मार्गों के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर केन्द्रीय गोटरथान अधिनियम, 1988 की धारा-112 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- 1377 दिनांक 06.04.2018 समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा यथावत लागू रहेगी।

पूजा नयाल,

सहायक सम्बागीय परिवहन अधिकारी,
प्रशासन, उच्चमंसिंह नगर।

**कार्यालय सहायक सम्मानीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), रुडकी
जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड**

अधिसूचना

22 जुलाई, 2023 ₹०

पत्राक-421/गति सीमा निर्धारण/2023-केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-112 की उपधारा-(2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे प्राधिकारी का जो इस निभित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा-116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात विन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेंगी जो ठीक समझे।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम-180 में वर्णित है कि किसी नगर, नगर पालिका या नगर पंचायत एवं भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतः मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह एवित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे रथान या भार्ग पर या उसके निकट, जहाँ वे लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 की उपधारा-(2) के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम-180 में प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुए रुडकी क्षेत्रान्तर्गत से होकर निकलने/चलने वाले ऐसे मार्ग या मार्गों के अंश पर, जो नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत की अधिकारिता से बाहर हो, संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गतिसीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है।

માર્ગ કા નામ	દૂરી	મધ્યમ/મારી વાહન હેતુ અધિકતમ ગતિ સીમા (કિલો/ઘણ્ટા)	હલ્ક ઘાર પહોંચા વાહન હેતુ અધિકતમ ગતિ સીમા (કિલો/ઘણ્ટા)	શિપહિયા વાહન હેતુ અધિકતમ ગતિ સીમા (કિલો/ઘણ્ટા)	દુધહિયા વાહન હેતુ અધિકતમ ગતિ સીમા (કિલો/ઘણ્ટા)
NH 334 (ANPR Location/ Joint Checkpost Narwari સ્થે 500 મીઠો આગે એવે 500 મીઠો પીછે)	01 કિલો	60	80	25	60
NH 344 (ANPR Location/ Mandawar સ્થે 600 મીઠો આગે એવે 600 મીઠો પીછે)	01 કિલો	60	80	25	60

ગતિ સમ્વન્ધી ઉપરોક્ત પ્રતિબન્ધ નિર્માલિંગિત શર્તો કે અધીન પ્રભાવી હોગાની

- સોટરયાન અધિનિયમ, 1988 કી ધારા-118 મેં વિનિર્દિષ્ટ યાત્રાયાત ઘિન્હ/સાઇન બોર્ડ પ્રતીશન્ધિત રથાન રો 500 મીટર પહલે વ બાદ મેં જગહ-જગહ પર આઈઓઆરોસીઓ કોડ કે સાનકાનુસાર સમ્વન્ધિત રલ્ડબ્રેક કે સ્થામિત્ર યાલે વિભાગ દ્વારા ઇસ પ્રકાર લગાયા જાયેગા કે વાહન ઘાલકો કે ઇસકી જાનકારી વ જ્ઞાન ભલિ-ભર્તિ હો સકેં।
- ઉત્ત પ્રતિબન્ધ કેન્દ્રીય સોટરયાન નિયમાદલી, 1989 કે વિનિર્દિષ્ટ નિર્મ પ્રકાર કે વાહનોને પર લાગૂ નહીં હોગાની।
 - (અ) અગ્રનિશમન વાહન।
 - (બા) એમ્બુલેન્સ।
 - (બ્દી) પુલિસ વાહન
 - (દ્વિ) વગ્નૂન એવ વ્યવસ્થા બનાયે રહ્યાને મેં લગે સૈચય બલ તથા અર્દ સૈચય બલ કે લિએ પ્રયુક્તા હોને વાળે વાહન।
 - (ચુ) પ્રાથ્મક વાપદા કે પ્રદાન કે લિએ પ્રયુક્તા વાહન।

એલ્યુન રોક્સી,

સહાયક સમ્માગીય પરિવહન અધિકારી,
(પ્રશાસન), રૂડકી।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

फलकी, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2023 ई० (आवण 21, 1945 शक सम्बत)

भाग ७

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुचित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापियां
भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

आदेश

27 जुलाई, 2023 ई०

सं.78/उत्तराखण्ड-वि.स /37/2022/सी.ई.एम.एस.-।।—यतः उत्तराखण्ड राज्य की 37-पीडी (अ0जा०) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 आधेसूचना नं. 464/उत्तराखण्ड-वि०स०/2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी।

यहांसोबत प्रसिद्धित अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अध्यर्थी की, जिर्वाचित अध्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 37- पीडी (अ0जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम, 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पीडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782/XXV-53/2022 के जरिए अंग्रेजित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री हरि कुमार, जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 37- पीडी (अ0जा०) से लड़ने वाले अध्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पीडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन अधीन द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 कैनियम 89 के उप नियम (5) के मत्तेगत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत महीने करने के लिए श्री हरि कुमार, को कारण बताजी नीटिस से 76/उत्तराखण्ड-वि. स./37/2022/सी.ई.एम.एस. III, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचितों का सचालन नियम 1961 के नियम 89 के उपर नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताको नोटिस के जरिए श्री हरि कुमार, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों की स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अस्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वाय अपने पत्र संख्या 1662/29- E E/2022 दिनांक 29.11.2022 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं० 891/XXV-22(II)/2008 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा अप्रैषित कर आयोग को सूचना दी गई कि सत्ता नोटिस अस्यर्थी के मार्द गणेश लाल द्वारा दिनांक 07.11.2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यहाँ, जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा अपने पत्र संख्या 1662/29-ई/2022 दिनांक 29.11.2022 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी पत्र सं० 891/XXV-22(II)/2008 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा अप्रैषित कर गयी गई अनुपूरक रिपोर्ट एवं सर्वीक्षा रिपोर्ट एवं पत्र संख्या 497/29-EE/2022 दिनांक 27.06.2023 द्वारा आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ने यह बताया गया है कि श्री हरि कुमार, ने न तो कोई भी अस्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्बन्ध नोटिस भिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यहाँ, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री हरि कुमार, निर्वाचन छात्रों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अवक्षालीनता ही नहीं है; और

यहाँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि-

"यदि निर्वाचित आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(घ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित नहीं रखता है, तो निर्वाचित आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

यहाँ, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 37- पौड़ी (अ०आ०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन जल्दी बाले अस्यर्थी श्री हरि कुमार, निकासी ग्राम-सिंगोरी, पौ०- सिंगोरी पट्टी कहलस्यू, तहसील- श्रीनगर, जिला- पौड़ी गढ़वाल। को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अवक्षालीनता के लिए निरहित है।

विनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
प्रताप सिंह शाह,
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

July 27, 2023

No. 76/Uttarakhand-LA/37/2022/CEMS-III--WHEREAS, the General Election to 37-Pauri (SC) Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No 464/Uttarakhand-LA/2022 dated 21st January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and

WHEREAS, the result of the said election along with 37-Pauri (SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022, and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Pauri Garhwal, Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer Uttarakhand vide their letter No 2782/XXV-53/2022, dated 22nd April, 2021, Sh. Hari Kumar, a contesting candidate of Uttarakhand from 37-Pauri (SC) Assembly Constituency of Uttarakhand, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer Pauri Garhwal, Uttarakhand and the Chief Electoral Officer Uttarakhand, a Show-Cause notice, 76/Uttarakhand-LA/2022/37/CEMS-III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Hari Kumar, for not lodging the account of Election Expenses and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 20.10.2022 Sh. Hari Kumar, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice, and

WHEREAS, the said notice was received by the candidate's brother Sh. Ganesh Lal, on 07.11.2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Pauri Garhwal, vide its letter 1662/29-E E/2022 dated 29.11.2022, forwarded by Chief Electoral Officer, Uttarakhand, letter no.891/XXV-22(II)/2008 date 15.06.2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Pauri Garhwal, in his Supplementary Report vide its letter No. 1662/29-E E/2022 dated 29.11.2022, forwarded by Chief Electoral Officer Uttarakhand, letter no. 891/XXV-22(II)/2008 dated 15.06.2023 and District Election Officer, Pauri Garhwal letter No 497/29-EE/2022 dated 27.06.2023 has reported that Sh. Hari Kumar has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further after receipt of the due notice of the Election Commission of India he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure. and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Hari Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

'If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order'.

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 the Election Commission of India hereby declares Sh. Hari Kumar resident of Village-Singori, P.O. Singori Patti Katulsyun, Tehsil- Dehradoon District- Pauri Garhwal, a contesting candidate from 37-Pauri (SC) Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India

By Order

PRATAP SINGH SHAH,
Joint Chief Electoral Officer,
Uttarakhand.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुडकी, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 21, 1945 शक समवत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक पिचापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, धारचूला (पिथौरागढ़)

लाइसेन्स शुल्क-1916 की धारा 298

11 मई, 2023 ई0

पत्रांक -771/लाइसेन्स संशोधन उपविधि/शासकीय प्रकाशन/2023-24 कार्यालय नगर पालिका परिषद् धारचूला, द्वारा धू०पी० म्यूनिसपैलटीज एकट 1916 की धारा 298 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पालिका अपनी सीमा के अन्दर दुकानों एवं विभिन्न व्यवसायियों को नियन्त्रित करने के लिए नगर पालिका परिषद् धारचूला द्वारा लाइसेन्स एवं अन्य शुल्क के उपनियम नियमानुसार तैयार किये गये थे जिसका शासकीय गजट तैयार किया जा चुका है परन्तु कतिपय व्यवसायियों की आपत्ति को बोर्ड द्वारा सुना गया नगर पालिका परिषद् बोर्ड की बैठक दिनांक 16.11.2022 के प्रस्ताव संख्या 21 में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्रकाशित लाइसेन्स एवं अन्य शुल्क में संशोधन किया जाये नगर पालिका परिषद् धारचूला द्वारा संशोधित सूची तैयार कर ली गई है। जिसे इस विज्ञाप्ति के 30 दिन अन्दर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने हैं। नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्रम संख्या	मद/व्यवसाय का नाम	संसोधित उपरान्त प्रस्तावित दर (रुपया)	वर्तमान में प्रस्तावित दरे
(क)	खाद्य पदार्थ व्यवसाय		
1.	किराने की दुकान	700.00	—
2.	थोक किराना	1500.00	—
3.	पान की दुकान/अन्य सामग्री	800.00	—
4.	रेस्टोरेन्ट (चाट, छोले, खाद्य, नाश्ता)	500.00	—
5.	मोजनालाय शेटे खुमचौ (चावल, वाल)	600.00	—
6.	सस्ते गल्ले की दुकान	700.00	—
(ख)	रेस्टोरेन्ट (मोजनालाय एवं मिठाई)		
7.	गोजनालाय	1000.00	—
8.	पर्यटक आदास गृह	4000.00	—
9.	चाय, बिस्कुट	300.00	—
10.	फौलिंग	1000.00	—
11.	हलवाई	600.00	—
12.	चॉट, बताशा	300.00	—
13.	झार्फुड थोक	800.00	—
14.	झार्फुड फूटकर	600.00	—
15.	आटा घरकी/तिलहन	1000.00	—
16.	ब्रेकरी/बिस्कुट फैक्टरी	900.00	—
17.	गोसाले थोक विक्रेता	3000.00	—
18.	मसाले फूटकर विक्रेता	600.00	—
19.	जूस कोर्नर	500.00	—
20.	जनरल रसोर (बड़ा)	1500.00	—
21.	जनरल रसोर (छोटा)	700.00	—
22.	सब्जी की दुकान	600.00	—
23.	सब्जी का गोदान	2000.00	—
(ग)	मदिशा की दुकान		
24.	शराब/वियर की दुकान	30000.00	—
25.	वियर बार	15000.00	—
(घ)	इलैक्ट्रिक/इलैक्ट्रोनिक्स व्यवसाय		
26.	इलैक्ट्रिक की दुकान	1000.00	—
27.	इलैक्ट्रोनिक्स की दुकान	2000.00	—
28.	इलैक्ट्रोनिक्स मरम्मत की दुकान	800.00	—
29.	फैब्रिल नेटवर्क	7000.00	—
30.	जनरेटर एवं अन्य उपकरण	500.00	—
31.	डीजेओ/साउन्ड सर्विस	1500.00	—
32.	टैन्ट हाउस	2500.00	—
33.	एफ.एम. टावर	10000.00	—
34.	कैसेट एवं डिविंग सेन्टर	500.00	—
35.	वैलिंग मशीन	700.00	—
36.	मोबाइल रिपरिंग की दुकान	500.00	—
37.	मोबाइल टावर	10000.00	—
38.	मोबाइल की दुकान	800.00	—
39.	इटरनेट कैफे	800.00	—
40.	पी०सी०ओ०	500.00	—

41.	कम्प्यूटर प्रेसिल्सन केन्द्र	1000.00	
42.	कम्प्यूटर विक्रेता	2000.00	
43.	कम्प्यूटर रिपरिंग सेन्टर	1000.00	
44.	घड़ी साज	200.00	
45.	प्रिंटिंग प्रेस	1000.00	
46.	फोटो लैब	800.00	
47.	फोटो ग्राफर	800.00	
48.	फोटो स्टेट/लेमिनेशन	800.00	
49.	फोटो फॉर्मिंग	300.00	
50.	गिल चौखट/वैलिंग की दुकान	1500.00	
51.	आरा मशीन	2500.00	
(८)	वाहन व्यवसाय		
52.	दो पहिया वाहन शॉर्लम	3500.00	
53.	चार पहिया वाहन शॉर्लम	6000.00	
54.	याकशॉप (दो पहिया)	600.00	
55.	याकशॉप(चार पहिया)	1200.00	
56.	मोटर साट्स(दो पहिया)	600.00	
57.	मोटर साट्स(चार पहिया)	1000.00	
58.	टायर्स की दुकान	800.00	
59.	गाड़ी की धुलाई	1000.00	
60.	ट्रांसपोर्ट व्यवसाय	3000.00	
61.	पेट्रोल पम्प	12000.00	
62.	गोटर इंजिनिंग सेन्टर	1000.00	
63.	मिट्टी के तेल की दुकान	6000.00	
64.	साईकिल स्टोर	700.00	
65.	साईकिल नरमता की दुकान	250.00	
(९)	मेडिकल व्यवसाय		
66.	चश्मे की दुकान	800.00	
67.	दॉतो का अस्पताल	1200.00	
68.	पैथोलॉजी सेन्टर	1000.00	
69.	दयाई की दुकान(आयुर्वेदिक)	1000.00	
70.	दयाई की दुकान(एलोपथिक)	1500.00	
71.	दयाई की दुकान(होम्योपेथिक)	1600.00	
(१०)	होटल व्यवसाय		
72.	आवासीय होटल पांच कक्ष तक	1500.00	
73.	आवासीय होटल दस कक्ष तक	2000.00	
74.	आवासीय होटल दस कक्ष से अधिक	3500.00	
75.	आवासीय होटल एवं बारात घर सहित	6000.00	
76.	बैंकट हॉल बारात घर	4000.00	
77.	गिलन केन्द्र(बैंकट हॉल)	4000.00	
(११)	कपड़ा व्यवसाय		
78.	कपड़ा व्यापारी थोक	5000.00	
79.	कपड़ा व्यापारी फुटकर पक्की दुकान	1500.00	
80.	कपड़ा व्यापारी खोखा दुकान	1000.00	
81.	रेडिमेंड पुराने कपड़े की दुकान	600.00	
(१२)	कपड़ा रेडिमेंड की दुकान थोक/फुटकर	1500.00	
82.	ऊनी/रेडीमेंड मार्मन्टस (थोक/फुटकर)की दुकान	2000.00	
83.	रेडिमेंड कपड़े की पक्की दुकान	1000.00	

81.	रेडीमैंड कपड़े की दुकान (खोखा)	800.00	—
82.	खई गदवे रजाई फी दुकान	1000.00	—
83.	खई गदवे रजाई धुनाई एवं बुनवाई	1200.00	—
(अ)	बर्तन व्यवसाय		
84.	बर्तन व्यापारी	1000.00	—
(अ)	मांस विक्रय		
85.	बकरी बकरा लाइसेन्स शुल्क	1200.00	—
86.	मुर्गा मुर्गी लाइसेन्स शुल्क	1200.00	—
87.	सुअर मांस की दुकान	1200.00	—
88.	मछली की दुकान	1000.00	—
(ट)	पशु वध शुल्क		
89.	बकरी बकरा प्रतिनग	50.00	—
90.	मुर्गा मुर्गी— मछली व्यवसाय प्रतिनिधि शुल्क	60.00	—
91.	सुअर प्रतिनग शुल्क	50.00	—
(व)	अन्य व्यवसाय		
92.	सीमोट/स्तरिया/ईट/टाइल्स/हार्डेयर विक्रेता	2000.00	—
93.	हार्डेयर की दुकान	1000.00	—
94.	फर्नीचर की दुकान	1500.00	—
95.	फर्नीचर गैकर्स	1200.00	—
96.	गव्वल/टाइल्स की दुकान	1200.00	—
97.	बदासा मरम्मत की दुकान	500.00	—
98.	शीशा ग्लास सेन्टर/प्लाईवुड की दुकान	1200.00	—
99.	अलगारी/बॉक्स स्टोल आयरन वकर्स	1000.00	—
100.	ग्रिल/चौखट/स्टील वकर्स	1000.00	—
101.	फारपैन्टर	1200.00	—
102.	शाटरिंग हाउस	1000.00	—
103.	मिठाई के बने मैकर्स	2000.00	—
104.	टेलर मास्टर (दो मशीन) तक	400.00	—
105.	टेलर गास्टर (दो मशीन) से अधिक	800.00	—
106.	पौ०को० टेलर सेन्टर	500.00	—
107.	झाईकलीनर्स	1000.00	—
108.	बारबर की दुकान दो कुसों लक	300.00	—
109.	बारबर दो दुकान दो कुसों की अधिक	500.00	—
110.	होडिंग (4*4)फिट तक	400.00 प्रति वर्ग फिट	—
111.	होडिंग (4*4)फिट से अधिक	800.00 प्रति वर्ग फिट	—
112.	बुक सेलर	1000.00	—
113.	झापट मैन	800.00	—
114.	जूता चप्पल थोक बिक्रेता	1500.00	—
115.	जूता चप्पल	1000.00	—
116.	बिसात की दुकान (खोखा)	500.00	—
117.	बिसात की दुकान (पक्की दुकान)	1000.00	—
118.	श्रगार केन्द्र/कार्सोटिक/अस्थाई फड़ में	1000.00 / 500	—
119.	ब्लूटी पालर	1000.00	—
120.	स्वर्जकर	1500.00	—
121.	लौहार	150.00	—
122.	मोची फुटपात	100.00	—
123.	घोबी	500.00	—

124.	व्यायाम शाला	500.00	
125.	साईन बोर्ड की दुकान	600.00	-
126.	पैटर्स/आटर्स वर्किंग	600.00	-
127.	चाबी छल्ला बनाने की मशीन	500.00	-
128.	बीज गोदाम	500.00	-
129.	स्टोप शाता	500.00	-
130.	डलिया सूपा	500.00	-
131.	बैन्ड	7500.00	-
132.	मल्लेदारी	100.00	-
133.	फोरी	300.00	-
134.	घोड़े खच्चर प्रतिनग	200.00	-
135.	रिक्षा	200.00	-
136.	डाय डला	200.00	-
137.	कबाड़ी की दुकान	1000.00	-
138.	कार्यालय एडवोकेट	1200.00	-
139.	खेल पुरुस्कार की दुकान	1000.00	-
140.	विद्यियो गैन्स	1000.00	-
141.	व्यवसाय प्राविक्षण संस्थान	2000.00	-
142.	अखबार पत्रिका विक्रेता/अन्य सामग्री विक्रेता	1000.00	-
143.	प्रैपटी डिलर	5000.00	-
144.	कोरिएटर सेन्टर	500.00	-
145.	पार्किंग शुल्क (चौपहिया वाहन)प्रतिकाहन/प्रति धंटा	20.00	-
146.	पार्किंग शुल्क (दोपहिया वाहन)प्रतिवाहन/प्रति धंटा	10.00	-
147.	पार्किंग शुल्क (छः पाहिया वाहन)प्रतिवाहन/प्रति धंटा	30.00	-
148.	विलियट्स गैम	3000.00	-
149.	सिलाइंटटन, ब सुई धारे के अन्य सामग्री	800.00	-
150.	मॉल	3000.00	-
151.	एकाधिक गल्टीपल दुकान	1500.00	-
152.	भूमि हरतानारण शुल्क	3000.00	-
153.	कुत्तो लाईरोल्स शुल्क	500.00	-
154.	विलम्ब शुल्क	10 प्रतिशत	-
155.	दगड़ी हाउस (कुत्तो वा शुल्क)	200.00	-
156.	आयासा जानवर शुल्क	2000.00	-
157.	आइसकीम ठेला शुल्क	300.00	-
158.	डाउन पार्किंग चालान फीस	2500.00	-
159.	एन्सर रजिस्ट्रेशन शुल्क	1000.00	-
160.	पालतू कुत्ता रजिस्ट्रेशन शुल्क	500.00	-
161.	रोड कंट्री शुल्क	100.00प्रति वर्ग फीट	-
162.	राज बिल्डी रजिस्ट्रेशन शुल्क	1200.00	-
163.	गैस स्टोप/कुकर/मशीन आदि मरम्मत कार्य	500.00	-
164.	छूट (समय अन्तर्गत जमा करने पर)	5 प्रतिशत	-
165.	सीएसएसोसेन्टर	1200.00	-
166.	बैंक एवं अन्य विभाग सफाई कर	5000.00	-
167.	गैस आफिस	2500.00	-
168.	गैस वितरण ठेकेदार	1500.00	-
169.	ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन शुल्क	3000.00	-

पी०एस०वोरा,

अधिकारी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, धारचूला,

(पिथौरागढ़)

राजेश्वरी देवी,

अध्यक्ष,

नगर पालिका परिषद, धारचूला,

(पिथौरागढ़)

કાર્યાલય નગર પંચાયત બેરીનાગ, (પિથૌરાગઢ)

વિજ્ઞાપ્તિ

24 સિત્તમ્બર, 2021 ઈંઝ

પત્રાંક 2065/સેટેજ મૈનેજમેન્ટ-ઉપનિયષ્ટ/2021 22 સર્વસાધારણ કો સૂચિત કિયા જાતા હૈ કે માનવીય રાષ્ટ્રીય હરિત પ્રાધિકરણ દ્વારા આવેદન સાઠે-10/2015 દિનાંક 10.12.2015 કે આવેદન કે અનુપાલન મેં એવું નગર પાલિકા અધિનિયમ, 1916 (યથાપ્રવૃત્ત ઉત્તરાખંડ રાજ્ય મેં) કી ધારા 276 મેં દિયે ગયે પ્રાધિકારોને કે અનુસાર તથા ધારા 298 કે ખંડ ઇં (ઘ) જ (ઘ) મેં દી ગયી ઉપનિયષ્ટ બનાયે જાને કી શક્તિયોનો કા પ્રયોગ કરતે હુએ તથા ધારા 301 કે અનુસર તી ગયી શક્તિ કે અનુસાર ઉપનિયષ્ટ કા પ્રકાશન કરાને હેતુ નગર પંચાયત બેરીનાગ કી બોર્ડ બૈઠક દિનાંક 10 સિત્તમ્બર, 2021 કે પ્રસ્તાવ સખ્યા 04 દ્વારા રાખ્યું સમાપ્ત સે પારિત પ્રસ્તાવ કે અનુસાર ઉપનિયષ્ટ 'પ્રોટોકોલ ફાર સેટેજ મૈનેજમેન્ટ' ઉપનિયષ્ટ 2021 બનાયે જાને કી રીક્વીકૃતિ ઉપસાન્ત થહ વિજ્ઞાપ્તિ ઇસ આશાય સે આપણી/સુઝાદ ચાહને હેતુ પ્રકાશિત કી જા રહી હૈ, જિસસે વ્યક્તિયોનો પર ઇસકા પ્રમાણ પઢને જા રહા હૈ

અતઃ લોક હિત મેં સુયથા સુરક્ષા એવું નિયંત્રણ થ વિનિયગન કરને હેતુ પ્રોટોકોલ ફાર સેટેજ મૈનેજમેન્ટ ઉપનિયષ્ટ-2021 મેં યદિ કિસી સંસ્થા વ્યક્તિ, વ્યક્તિ વિશે ફર્મ ઉદ્યોગ કો કોર્ડ આપિત્ત/સુઝાદ હો તો યે ઇસ વિજ્ઞાપ્તિ કી પ્રકાશન તિથિ સે 30 દિન કે ભીતર અપની હિન્દિત આપણી કાર્યાલય નગર પંચાયત બેરીનાગ જિલા પિથૌરાગઢ મેં પ્રસ્તુત કર સકતા હૈ. રામય પંચાયત પ્રાપ્ત હોને વાતી આપણી અધયા સુઝાદ પર કિસી ભી દશા મેં વિચાર નહીં કિયા જા સકેગા। જો નિન્દાવતું હૈને:-

પરિભાષા:-

૧-સંક્ષિપ્ત નામ ઔર લાગુ હોને કી તારીખ:-યહ ઉપનિયષ્ટ નગર પંચાયત બેરીનાગ ફાર સેટેજ મૈનેજમેન્ટ ઉપનિયષ્ટ-2021, નિયમાબદી કબુલાયેગી જો કે વિજ્ઞાપ્તિ ભરકારી ગાંડ ઉત્તરાખંડ મેં પ્રકાશિત હોને કી તિથિ સે પ્રભાગી હોએ હોએ। યહ ઉપનિયષ્ટ નગર પંચાયત બેરીનાગ કી સીમા કે ભીતર લાગુ હોએ

નગર પંચાયત-નગર પંચાયત કા આશાય નગર પંચાયત બેરીનાગ જિલા પિથૌરાગઢ કે ૦૭ થાર્ડ્સ કી સીમા સે હૈને,

૩-અધિશાસી અધિકારી:-અધિશાસી અધિકારી કા આશાય નગર પંચાયત બેરીનાગ કે કાર્યપાલક અધિકારી સે હૈ।

૪-અધ્યક્ષ- અધ્યક્ષ કા આશાય નગર પંચાયત બેરીનાગ કે નિર્વાચિત બોર્ડ સે હૈને, બોર્ડ કે કાર્યકલાપ સમાપ્ત હો જાને પર અધ્યક્ષ કે રથાન પર પ્રશાસક/ઉપચિલાધિકારી અધ્યક્ષ કે રૂપ મેં પ્રભાગી અધિકારી સે હૈને

૫- સેટેજ મૈનેજમેન્ટ સેલ --સેટેજ મૈનેજમેન્ટ સેલ કા આશાય નગર પંચાયત બેરીનાગ મેં સરકારી સેથા કે શાસન દ્વારા નામિત અધિકારિયોનો કે જસ્તુ કી એક ગઠિત ઇકાઈ સે હૈને જો કે ભર્ટેજ મૈનેજમેન્ટ સેલ કહુલાયેગા। જિસકે અધ્યક્ષ ઉપચિલાધિકારી બેરીનાગ હોએ તથા અધિશાસી અધિકારી નગર પંચાયત બેરીનાગ સદસ્ય સંચિવ હોએ ઔર અધિશાસી અભિયન્તા જલ સરથાન પિથૌરાગઢ, અધિશાસી અભિયન્તા જલ નિગમ ગંગોલીહાટ તથા મુખ્ય ધિકિસા અધિકારી પિથૌરાગઢ દ્વારા નામિત પ્રત્યેનિધિ, ક્ષેત્રીય અધિકારી ઉત્તરાખંડ પ્રદૂષણ નિયન્ત્રણ બોર્ડ હલ્ડાની, તથા અયસ અભિયન્તા લોનિઓનિયાગ બેરીનાગ નામિત સદસ્ય હોએ।

૧. શીર્ષક વિસ્તાર ઔર પ્રસંગ :- શાસ્ત્ર કા યહ અનુમદ રહા હૈ કે સીટિક ટૈંક ઔર અવધીય જો લિંગાયન સે સમ્વાચ્છિત હૈ, રથાનીય સંસ્થાનો દ્વારા વર્ષો સે અનુપાલન કિયા જા રહા હૈ, જિસકે સફલ સંચાલન હેતુ કુશાલ પ્રબન્ધન કી આવશ્યકતા હૈ। યહ ગહત્વપૂર્ણ હૈ, કે નગર મેં એક ઉચિત વૈજ્ઞાનિક પ્રબન્ધ કે મામલોનો મેં સેટેજ તકનીકી કા અનુપાલન કિયા જાતા હૈ તાકિ પર્યાવરણ કી સુરક્ષા કી દૃષ્ટિગત રખતે હુએ સેટેજ/ફીકલ સ્લાઝ સીટિક ટૈંક ગઢા શૌચાલય પર્યાવરણ નદી એવ અન્ય પાની આદી ઓત કો પ્રદૂષિત ન કરે।

1.1— राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबन्धकीय नीति—

इस महत्पूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास भवित्वालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है : राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस सैटिकोन के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तान्दुलस्ता और जीवित हने रहे एवं अच्छी सफाई भी बनी रहे तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेटेज प्रबन्धक, ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सकें और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें विशेषकर मरीयों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ वातावरण प्रसान्न प्राथमिकता और ज्ञान, निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इस सेवाओं का समस्त क्षेत्रों में हो सके और कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एक वास्तविक प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में यनी पह सकें।

1.2 चत्तराखण्ड में सेटेज प्रबन्धक प्रोटोकाल—

माननीय एन०जी०टी आदेश सं०-१०/२००५ दिनांक १०-१२-२०१८ में निम्न निर्देश दिये गये हैं। जो कि चत्तराखण्ड में सेटेज प्रबन्ध के सम्बन्ध में है। 'उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा' यह आकान्तिक करने के लिये कि सीधरेज की निकासी यो सामान्य सैटिक टैक में या बायोडाइज़ास्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये और उसका समुचित प्रबन्ध किया जाये। उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह नियुक्त विकासनों को वितरित की जाये और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रबन्धन एक भागीदारी समर्थित निकाय नगर पंचायत बैशीनाग की होगी। उपरोक्त को अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीधरेज अधिनियम १९७५/नगर पालिका अधिनियम १९१६ भारी विकास निवेशालय यो कि उत्तराखण्ड जल संरक्षण के सम्बन्ध से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सैटिक प्रबन्ध तैयार किया है जो कि संधिय शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है। ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश सं० ५९७ / (IV (2)-१०वि०-२०१७-५० (सं०) / १६ दिनांक २२-०८-२०१७ राज्य का सैटिक प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह विर्क्षन करता है ताकि वैश्वानिक सैटिक प्रबन्धन प्रयोग रहे जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, संपर्क, सैटिक / फीकल स्लज का नियन्ताश्वरूप और पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रकार एस्ट विल निर्देश इस प्रोटोकाल के हैं, कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वह अपने निकाय में सैटिक प्रबन्धन का उच्चीयता कर सकें और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी कियान्वयन कि लिये और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेटेज मैनेजमेंट फैल का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत बैशीनाग, पैथजल निगम, जल संरक्षण होंगे।

२—नगरीय उपकानून / "फीकल स्लज एवं सेटेज का नियमितीकरण":—सेटेज प्रबन्धन प्रोटोकाल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के भा०सं-५९७ / (IV (2)-१०वि०-२०१७-५० (सं०) / १६ विनांक २२-०८-२०१७ एवं समरस लागू होने वाले नियम या कानून या समय-२ पर ज्ञासन संशोधित नियम या नियमाधाली नगर पंचायत बैशीनाग जनपद पिथौरागढ़ नियमित ढांचों रियल करने एकत्र करने, परिवहन और सेटेज और फीकल स्लज के परिवहन एवं नियन्ताश्वरूप हेतु जैसा कि वर्णित है। फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबन्धन उपनियम को अन्तर्गत जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत बैशीनाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

उद्देश्य एवं कार्यक्रम :— इस नियमाधाली के उद्देश्य एवं कार्य निम्नावत् हैं—

1. निर्भाग सैटिक टैक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ़े परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाव जो कि स्लेज और सेटेज से सम्बन्धित है,
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना यो कि सैटिक टैक और शौचालय के गढ़े से और फीकल स्लज एवं सेटेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इस निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सकें।
3. संचित नियन्ताश्वरूप करना और मौतानी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेटेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है।
5. निजि और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना,

4- एकत्रीकरण परिवहन इलाज सैटिक के खुर्द खुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना।

4-(1) सैटिक टैंक और सैटेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना:-

सैटिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुंच गया है या बार-बार के आखिर में जो डिजाइन है जो कोई भी पहले आये,

जबकि स्लज को सुखाना और सैटिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना/मैकेनिकल वैक्यूम टैक्स का उपयोग (जो नगर पंचायत बैरीनाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है) नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैटिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिये।

सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सैटेज प्रबन्ध प्रोटोकॉल में वर्णित है को सैटिक टैंक के खाली करते समय और सैटेज के परिवहन के समय इस नियम पर सख्ती से पालन किया जाना चाहिये,

4 (2) सैटेज/फीकल स्लज का परिवहन

1- फिकल स्लज और सैटेज टांक्सपोर्टर वाहन पर सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तराधारी होंगे जैसा कि सभ्य-समय पर सैटेज मैनेजमेन्ट से (एस०एम०गी०) द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(2) फिकल स्लज और सैटेज फिकल निर्माता यह आशयासन देंगे कि:-

(अ) पंजीकृत संग्रह याइन जिसके अन्तर्गत सभरत उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेंगे फिकल स्लज और सैटेज हेतु जो छिप निरोधी होगा और फिकल स्लज और सैटेज हेतु तालाबन्द रहेगा। और लागू किये जाने योग्य मानवण्ड का अनुपालन करेंगे।

(ब) कोई भी टैंक और उपकरण जो कि फिकल स्लज और सैटेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नहीं करेगा।

4(3) सैटेज का निष्पादन और इलाज-शाय्य सैटेज मैनेजमेन्ट प्रोटोकॉल के अनुसार नगर पंचायत बैरीनाग की अपनी एक इकाई होगी, जिसके अन्तर्गत पृथक भे एक अलग सैटेज ट्रीटमेन्ट प्लाट फा निर्माण किया जायेगा।

5--सुरक्षा स्पष्टाय :-

(1) उचित तकनीकि संयन्त्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहिये।

(2) फिकल स्लज और सैटेज ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करें :-

- समस्त मल निस्तारण कर्मधारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीरेटर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत काथे की लम्बाई तक पूरा कोटेड हिपोकिन, लोयर, रेवर बूट, थ्रेहर का मार्क और खोड़े की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगत जैसा कि मैनुफॉर्मर और उनके मुनाफास नियम 2013 में उत्तिलिखित है।
- समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये
- समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण के प्रयोग की जिस दी जानी चाहिये
- ग्रथग सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैम्प और अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते हैं। इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।
- सैटिक टैंक पिट लैट्रिन में जब काम चल रहा हो उस समय धुगपान पूर्णतः चर्जित है,
- मल निस्तारण कार्यकर्ता सैटिक टैंक में और धैत्यालय गढ़े में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को आना जाना रखेंगे जो कि इस कार्य का बुरा करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

➤ बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जायें ताकि ये टैंक के स्कू और ताले से सुरक्षित रहें, कर्मचारी सावधान रहेंगे जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार होता है। या मैं होल का आव्हान दूटने से बचा रहे।

➤ उपभोक्ता लागत को मासिक स्थिराई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा अथवा एवं क्षेत्र नगरीय पर्यावरण की सभुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा, करना होगा।

६- सेटेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन-

६.१ नगर पंचायत, बेरीनाग वाहन को दर्ज करेगा और इसका लाइसेन्स निर्गत करेगा, निजी व्यवसायियों के लिए जिनके पास मीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाइसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह अशान्ति करेगा यह वाहन उचित उपकरण और उचित सुरक्षा याप से सुरक्षित है, तथा मानकों के अनुरूप है, सेटेज ट्रान्सपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण करने हेतु नगर पंचायत, बेरीनाग के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ वाहन का परिवहन व परिवहन की प्रति ग्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दरकार होगा।

६.२ नगर पंचायत बेरीनाग सीमान्तरगत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेटेज ट्रान्सपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा। जो व्हीकल एस०एम०सी० के साथ इन प्रोटोकॉलों में पंजीकृत नहीं है

साइरी-१ पंजीकरण व्यय

अ-ग्रामीण पंजीकरण-	रु० 2000.00 प्रतिवाहन
इ-वार्षिक नीनीकरण-	रु० 1500.00 प्रतिवाहन
स-नाम परिवर्तन/स्वामी का परिवर्तन-	रु० 1000.00 प्रतिवाहन
ध-अन्य संस्कार आवश्यकतानुसार-	रु० 1500.00 प्रतिवाहन

७- उपभोक्ता लागत और इसका संचय-

७.१ इस क्षेत्र के समस्त मालिकों जो सेटिक टैंक और शौचालय के गवड़े जिसका गुणलान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पंचायत में फौकल रस्ते और सेटेज उपलब्धम में समय-समय पर कार्यान्वयन किया जाया है जो, कि सेटिक टैंक के भरने शौचालय के गवड़े परिवहन और फिल रस्ते एवं सेटेज के उपाय हेतु है।

७.२ नगर पंचायत बेरीनाग अपनी लागत से संबंधित करेगा कि समय-समय इससे सम्बन्धित है ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिल रस्ते व सेटेज के निष्कर्षन हेतु है

७.३ उपभोक्ता लागत क्षेत्र क्षेत्र के स्थायी एकत्र किये जाये जो निम्नलिखित है-

(अ)- उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रुप से नगर पंचायत बेरीनाग द्वारा वसूला जायेगा या नगर पंचायत, बेरीनाग के कोष में जमा किया जायेगा। जो कि सम्बंधित भवन/सेटिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा

सारणी-२ उपभोक्ता लागत

संख्या०	भवन का योग	प्रति वाहन लागत	कियाये की अधिकतम अवधि जो सेटिक टैंक एवं शौचालय गवड़े हेतु निर्धारित है	सारिक दण्ड ५ प्रतिवाहा की वर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1	टीनैल वाला मकान	4,000.00	कम से कम 2-3 वर्ष में एकवार जब 2 टैंक होते हैं 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार	200.00
2	अन्य समस्त आवास	4,000.00		200.00
3	बुकान	4,000.00		200.00
4	सरकारी/निजी कार्यालय	4,000.00		200.00
5	बैंक	4,000.00		200.00
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	4,000.00		200.00
7	रेस्टोरेंट	4,000.00		200.00
8	होटल/गेस्ट हाउस (1 से 10 कमरे)	4,000.00		200.00
9	धर्मशाला (3 से 25 कमरे)	4,000.00		200.00
10	सरकारी स्कूल/कॉलेज	4,000.00		200.00
11	निजी स्कूल/कॉलेज	4,000.00		200.00
12	व्हीकल नोरम	4,000.00		200.00

13	વિવાહ હોલ/ બૈંકટ હોલ	4,000.00		200.00
14	બાર	4,000.00		200.00
16	સરકારી હાસ્પિટલ	4,000.00		200.00
18	નર્સિંગ હોમ/ વ્હીનિક	4,000.00		200.00
17	પૈથોલોજી લેબ	4,000.00		200.00
18	નિર્જી અસ્પિટાલ 20 બૈંડ તક	4,000.00		200.00
19	અન્ય	4,000.00		200.00

નોટ— 1— ઉપરોક્ત ઉપમોયતા વ્યય સાકેતિક હૈ, ઔર ઉનકા નિર્ણય ઔર સ્વીકૃતિ નગર પંચાયત બેરીનાગ દ્વારા નિર્ણત કિર્ય જાયેગે।

2— મલ નિસ્તારણ સમયાવધિ મેં હોગા યા જવ ટૈંક 2/3 કી આપૂર્તિ કર દેશા હૈ। (જોસા કિ નગર પંચાયત, બેરીનાગ દ્વારા સ્વીકૃત હૈ)

3— ઉપમોયતા લાગત ૫ પ્રતિદિન વાર્ષિક વર સે અઠાઈ જાયેગી।

૪—ગેકેનિજ્જમ કા નિરોધણ, ક્રિયાન્વયન ઔર મજબૂતી દેના—

૪.૧ કોઈ ભી વ્યક્તિ જો એસ૦એમ૦સી૦ (સૈટિક મૈનેજમેન્ટ સેલ) / નગર પંચાયત, બેરીનાગ દ્વારા અધિકૃત હૈ, ઉસકો પૂર્ણ અધિકાર હોગા કિ વહ સૈટિક ટૈંક એં હર એક મકાન કે શીચાલાય, ગંડકે દા શામુદાયિક / સંસ્થાનત આવિ કા નિરીક્ષણ કરેગા

૪.૨ મલ નિસ્તારણ કા અનુયાલાન ન કરના જોસા કિ ઉપરોક્ત વર્ણિત હૈ જુર્માના અલગ સે લાંબાય જાયેગા ઔર જુર્માને સે પ્રાપ્ત ધનરાશી નગર પંચાયત છોડું મેં જમા હોગી।

૪.૩ નગર પંચાયત, બેરીનાગ ક્લેન્ન કે ટૈંક કે ખાલી હોને કા અભિલેખ રહેણે।

૪.૪ અધ્યેતના કાર્યક્રમ સમય-શરમય પર ચલાયા જાયેગા જો કિ પ્રત્યેક વ્યક્તિ, સરકાર યા નિર્જી વ્યયસાય કે પ્રશ્નિક્ષણ હેતુ હોગી, જો કિ સૈટિક ટૈંક બાયોલાઇઝેસ્ટર મલ નિસ્તારણ સૈટિક ટૈંક કા એકત્રીકરણ માટેની પરિયહન નિષ્પાદન ઔર સૈટિક કા ઈલાજ।

૫—દણ્ણ—

દણ્ણ કા ઢોચા ઉપકરણ રહિત / અકાર્યબીલ જીઓનોએલ૦ પ્રણાણી નિર્ધન વર્ગ કે શિકાયતો ફિકલ સ્લાઝ કા એકત્ર ને કરના ઔર સેટેજ ઈલાજ પ્લાટ કા / આઓનોએલ૦ કા રઝિસ્ટ્રેશન ન ફરના સુરક્ષિત ઉપય મલ નિસ્તારણ ગાંધિયો કો અનુપાલન ન કરના।

સારણી-૩ વણ્ણ

ક્રમ નંબર	શિકાયત કા પ્રકાર	વણ્ણ આ કાર્યવાહી વર્ષ પ્રપત્ર દુષ્ટા પકડી ગવી વર્ષ મેં એકવાર મલ નિસ્તારણ	વણ્ણ યા કાર્યવાહી વર્ષ મેં દોબાશ પકડી ગવી મલ નિસ્તારણ વાહન સે સમાવિષ્ટ	વણ્ણ યા કાર્યવાહી વર્ષ મેં તીસરે બાર પકડી ગવી ક્ષેત્ર ફાપ સે મૂલ નિસ્તારણ વાહન
1	લોગો કો ધોચનીય સેવા કો શિકાયત	2600.00	6000.00	તીન મહિને કે લિયે પરમિટ સેવા કો શિકાયત પર પરમિટ કા નિરસ્તીકરણ
2	સેટેજ / ફિકલ સ્લાઝ જોસા કિ ક્ષેત્ર કાર્ય ક્લેન્ન મેં	1000.00	6 માહ કે લિયે પરમિટ કો સ્થળગીત કરના	-
3	પંજીકરણ ન કરના / પંજીકરણ ના નિયોનીકરણ ન કરના	1000.00	2000.00	ઓર્ટોનો કો સંસ્તુતિ યાહોંને પંજીકરણ કો નિરસ્ત કરને હેતુ ૩ મહીને કે લિયે પરમિટ કો સ્થળગીત કરના / પરમિટ કા નિરસ્તીકરણ કે લિયે સ્થળગીત કરના

शक्ति/दण्ड

नगर पंचायत, बेरीनाग जिला-पिथौरागढ़ की सीमान्तर्गत 'प्रोटोकॉल फार सेटेज मैनेजमेन्ट' के अनुपालन हेतु मा० चाष्टीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं०-१०/२०१५ दिनांक १०.१२.२०१५ के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम-१९१८ की धारा २९९ (१) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरशासी जो प्रोटोकाल फार सेटेज मैनेजमेन्ट की उपरिक्षण की फिसी भी धारा का उल्लंघन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोष सिद्ध पाये जाने पर ₹० ५०००.०० (रु० पाँच हजार) का अर्थदण्ड किया जायेगा। उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रधम दोष सिद्ध होने की स्थिति में ₹० ५०००.०० (रु० पाँच हजार) के अतिरिक्त प्रतिदिन ₹० १००.०० (रु० एक सौ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।

शाहिद अली,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, बेरीनाग।

हेम पन्त,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, बेरीनाग।

कार्यालय नगर पंचायत केलाखेड़ा (ऊधम सिंह नगर)

14 जून, 2023 ई०

पत्रांक—263/न०प०/प्ला०अप०प्र०/2022—23—नगरपालिका अधिनियम १९१६ की धारा २९८ (घ) एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन सत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनाक १८ मार्च 2018 के द्वारा बनाये गये अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के अन्तर्गत नगर पंचायत केलाखेड़ा हेतु नगरपालिका अधिनियम १९१६ की धारा २९८ इ० (घ) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ (१९८६ का २९) की धारा ३, ६ एवं २६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन सत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनाक १८ मार्च 2018 द्वारा बनाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार गैं लागू किये जाने हेतु तैयार किये गए “प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, २०२२” बोर्ड बैठक दिनाक ०६—०६—२०२३ में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या—१३ के द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशन कराया जाना स्वीकार किया गया है।

उत्तरप्रदेश नगरपालिका अधिनियम १९१६ यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड, की धारा—३०१(२) के प्रयोजनार्थ नगर पंचायत केलाखेड़ा “प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, २०२२” का प्रकाशन सरकारी गजट उत्तराखण्ड में किया जाता है।

“प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, २०२२”

अध्याय-१

१. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:-

- (i) ये उप-नियम नगर पंचायत केलाखेड़ा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, २०२२ कानूनायेंगे।
- (ii) ये उप-नियम नगर पंचायत केलाखेड़ा के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
- (iii) ये उपनियम भेन्ट्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमित के आदेश के लिए अपने उत्पाद के विनिर्माण के लिए नियांतो-नुस्खा ईकाइयों या विशेष आर्थिक जोन की ईकाइयों पर लागू नहीं होगा परन्तु यह छट गुटावा, तम्बाकू और पान मसाला के पैकेजिंग में लगी ईकाइयों और अधिशेष या निराफूत अवशेष और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर भी लागू नहीं होगी।
२. ये उप-नियम नगर पंचायत केलाखेड़ा की अधिकारिता के भीतर उपलब्ध प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, विनिर्माता, उत्पादनकर्ता, आयातक ब्रांड के मानिक तथा उत्पयोगकर्ता पर लागू होगी।
३. परिभाषाएँ:- इन उपनियमों में जब तक कि सेवर्वें से अन्यथा अपेक्षित न हो—

 - (a) अधिनियम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ का २९) अधिप्रेत है।
 - (b) ब्रांड मानिक ऐसे व्यक्ति या कम्पनी से अधिप्रेत है जो किरी पंजीकृत ब्रांड लेबल के तहत कोई वस्तु बेचता है।
 - (c) किरी बैग से प्लास्टिक सामग्री या कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्री से बनाया, ले जाने या वस्तुयों तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त वींग अधिप्रेत है जिसमें स्वतं से जाने की विशिष्टता है किन्तु इसमें ऐसा वींग समिलित नहीं है जो ऐसी पैकेजिंग गठित करता है या अभिन्न भाग बनता है जिसमें मान को उपयोग के पूर्व सीक्ष किया जाता है।
 - (d) “वस्तु से” ऐसा सूर्त मद अधिप्रेत है जिसे छारीदा या बेचा जा सके और इसमें सभी पण्य माल या सौदा समिलित हैं।

(१) "कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई साक्साईड, जल, अकार्बनिक यौगिकों को कम्पोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कम्पोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य विशेषणीय या विशाल क्षमिता नहीं छोड़ती है।"

(२) "विघटन" से किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है।

(३) "विस्तारित उत्पादक दायित्व" से इसके जीवन तक उत्पाद के पर्यावरणीय रूप से मुद्रण के लिये उत्पादक का दायित्व अभिप्रेत है।

(४) "खाद्य पदार्थ" से द्रव, चूर्ण, टोस या अर्धठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है।

(५) "सुविधा" से प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, भण्डारण, पुनर्व्यवस्था, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपयोग किये जाने वाला परिसर अभिप्रेत है।

(६) "आयातकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आयात करता है या करने का द्वारा रखता है और जिसके पास आयात-गिरिजा करने का लाइसेन्स है जब सक उसे अन्यथा विशेष रूप से छुट नहीं दी गई हो।

(७) "संस्थागत अपशिष्ट जनित" से केन्द्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकारी विभाग, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शिक्षा के अन्य स्तर, संगठन, अकादमी, होटल, रेसरा, मॉल और गैरिपिंग परिसरों द्वारा अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवनों या अधिकृतों अभिप्रेत है और समिलित है।

(८) "विनिर्माता" से उत्पादक द्वारा कम्पी सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक की कम्पी सामग्री के उत्पादन में जगा व्यक्ति या ईकाई या अभिकरण अभिप्रेत है जो समिलित है।

(९) "बहुरारीय पैकेजिंग" के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री अभिप्रेत है और फाराज, कार्ड बोर्ड बहुलक्षण रामगिरि, धातिक भत्तहों या एल्युमिनियम पत्रियां जैसे या लो लेकिनेट के रूप में या भह-विश्विधन रूप में जैसे सामग्री के एक से अधिक सहज मुक्य हावड़ों के रूप में प्लास्टिक का कम से कम एक स्तर रखती है।

(१०) "प्लास्टिक" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलीइथाइलिनटेरफथलेट, उच्च घनत्व पोलीइथाइलिनविनाइल फम घनत्व फोसीइथाइलिन, पोली ग्रोपीलीन, पोलीस्टाइरिन रेसिन, एक्रीलीनोद्यायल-बूटाडाइन-प्टाइरिन जैसी वह सामग्री, पोलीपिनाइलीन आवसाइड, पोलीकार्बोनेट, पोलीबूटीलीन टेरेफथलेट जैसी उच्च पालिमर के आधारक तत्व अंतर्भूत हों।

(११) "प्लास्टिक चाबर" से प्लास्टिक चाबर अभिप्रेत है अर्थात् प्लास्टिक से बनी चबर।

(१२) "प्लास्टिक प्लास्टिक अपशिष्ट" से ऐसे किसी प्लास्टिक से अभिप्रेत है जिसे उपयोग के पश्चात या इच्छित उपयोग के पश्चात फैक दिया जाता है।

(१३) "उत्पादक" से केरीबैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक सीट या जैसे के विनिर्माण या आयात में जगा व्यक्ति अभिप्रेत है और प्लास्टिक सीट या जैसे या प्लास्टिक रीट के बनाये गये कवर या घस्तु की पैकेजिंग या दृक्कों के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर रहे उद्योग या व्यक्ति समिलित है।

(१४) "पुनर्व्यवस्था" नये उत्पाद उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नये उत्पाद या कम्पी सामग्री में प्रयोगात्मक करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है।

(१५) "रजिस्ट्रीकरण" से यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या सम्बद्ध प्रदूषण नियन्त्रण समिति में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है।

(१६) "पर्यावरण" का वही अर्थ होगा जो पर्यावरण (आजीविका का संरक्षण और पर्यावरण का विनियमन) अधिनियम 2014 (2014 का 7) की भारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में है।

(प) “शहरी स्थानीय निकाय” से नगर पंचायत केलाखेड़ा अभिषेत है समिलित है।

(फ) “अश्रुकृ प्लास्टिक” से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिषेत है जिसका पहले उपयोग नहीं किया गया। अपशिष्ट के साथ भी समिश्रित नहीं किया गया है।

(ब) अपशिष्ट जनित से प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था, भारतीय रेल, विमान पत्तन, बन्दरगाह और रहा कैन्टोनमेंट, जो अपशिष्ट प्लास्टिक पैदा करते हैं सहित रिहायरी और वाणिज्यिक स्थापना अभिषेत है और समिलित है।

(म) अपशिष्ट प्रबन्धन से प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की वृद्धि से सुरक्षित पहुंच से एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति, पुनर्व्यवस्था, कम्पोस्टिंग या व्यवन अभिषेत है।

(म) अपशिष्ट चुनने वाले से पुनर्व्यवस्था योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के चुनाव में स्वैच्छिक रूप से सगे या ग्राहिकृत किये गये व्यक्ति या एजेन्सियाँ, व्यक्तियों का समूह अभिषेत है।

(ग) घरमोहेट प्लास्टिक, जग ताप या अन्य साधन से उत्पादित सार्विक रूप से अगलनीय या असुलनीय उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है घरमोहेट एक प्रकार का प्लास्टिक है जो अपने भागों में रसायनिक संरक्षन के कारण रिसोर्स या रिशाइकिल नहीं किया जा सकता।

अध्याय-२

प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्धन-

४- नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्धन नियमित किया जायेगा-

(फ) प्लास्टिक कैरी बैग से अन्यथा प्लास्टिक- आशिष्ट जिसका रिसाइकिल किया जा सकता हो, नियमित प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाइकिल के राय चेनलाईज करेंगी और भारतीय भानक आईएल० 14534 . 1998 प्लास्टिक रिसाइकिलिंग के लिए सार्वदर्शन रामय- रामय पर यथा संदीधन के अनुरूप संपुष्ट करेंगी।

(छ) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट (प्राथमिक रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट जिसका आगे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता) सुधक नियमित या ऊर्जा प्राप्ति अथवा अपशिष्ट से तेल इत्यादि के लिए उपयोग हेतु प्रोत्साहित करेंगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विनियोगित प्रदूषण नियन्त्रण भानकों के अनुसार इन तकनीकियों का पालन किया जायेगा।

५- शर्तों का पूरा किया जाना- नगर पंचायत केलाखेड़ा का विचार है कि प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग शम्भीर पर्यावरणीय समास्यों उत्पन्न कर रहा है जिससे मानव एवं जीव जन्तुओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि नगर पंचायत केलाखेड़ा की सम्पूर्ण अधिकारिता में प्लास्टिक कैरी बैग विनियोग, आवाह, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर सेफ जागरूक जाय।

(I) कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत केलाखेड़ा की अधिकारिता में किसी भी भानक के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किये जिना, विनियोग आवाह, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग नहीं करेगा।

(II) दुकानदार, बैंडर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, व्यवसायी, हृकर, फेरीवाला सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी छाने या न छाने योग्य माल या सामग्रियों के यथा वितरण के लिए किसी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किये जिना, विनियोग आवाह, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग नहीं करेगा।

(III) बायोडिकल के लिए प्लास्टिक कैरी बैग, बीजांकुर के लिए उपयोग किया जाने वाला पालीबैग, प्लास्टिक सीट से बना प्लास्टिक सीट या ऐसी ही बस्तु का विनियोग, आवाह, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग तथा मल्टीलेयर पैकेजिंग नियमित जातों के अध्याधीन होगी। यथा-

१- बायोडिकल अपशिष्ट के भण्डारण के उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक कैरी बैग को इस उपचित्रित के घाविशानों से छूट प्राप्त होगी तथापि प्लास्टिक कैरी बैग मोटाई में ५० माइक्रोन से कम नहीं होगे और बायोडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन विधायली में इस सम्बन्ध में

किये गये प्राविधानों का भी पूरा भालन किया जाना चाहिए। वायोमेडिकल अपशिष्ट वाला प्लास्टिक कैरी बैगों का निपटारा वायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावची 2016 में किये गये प्रावश्यानों के अनुभालन में किया जाना चाहिए।

- 2 रिसाईफिल किये गये प्लास्टिक के बने उत्पादों का उपयोग खाने पीने के लिए तैयार भोज्य पदार्थों के भण्डारण, ले जाने, वितरण या पैकेजिंग के लिए नहीं किया जायेगा।
- 3 बर्जिन या रिसाईनिल किये गये प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर, उसकी मोटाई पर विचार किये दिना, नगर पंचायत कैजाखेड़ा की अधिकारिता में रोक लगेगी।
- 4 राज्य पर्यावरण एवं वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजांकुर की बृद्धि करने के लिए उपयोग किये गये पालीबैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम न हों और सभी उपयोग किये गये पालीबैगों का मुन संग्रहण एवं उनके गुरुकित निपटारों को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 5 निजी नसरियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजांकुर की बृद्धि के लिए उपयोग किये जाने वाले पालीबैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम न हो प्राईवेट नसरियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सर्वाधिक समवयवधि तक इन पालीबैगों का दोबारा उपयोग हो।
- 6 निजी तथा सरकारी नसरी को यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उपयोग किये गये पालीबैगों को एक स्थान पर संग्रह किया जाय तथा उसे नगर पंचायत को नियमित फीस का मुगालन कर दूसरात फर लाने।
- 7 प्लास्टिक सीट या ऐरी ही वस्तु जो मल्टीलेयर किये गये पैकेजिंग तथा वस्तुओं की पैकेजिंग चारैपैग के लिए उपयोग किये गये प्लास्टिक के बने कवर के अधिक राग न हों उनको छोड़कर जहां ऐरो प्लास्टिक सीट की मोटाई उत्पादों की कियाशीलता को कम करते हों की मोटाई 50 माइक्रोन से कम नहीं होंगी।
- 8 विनिर्मिता राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये दिना उत्पादकों को कम्ब माल के रूप में प्लारिट्रल का उपयोग किये जाने हेतु विधि या उपलब्ध या व्यक्तस्था नहीं करेगा।
- 9 पालक के रूप में उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक फैटेरियल का उपयोग गुदखा, तमाकू तथा यान मरालो के भण्डारण पैकिंग या विक्रय के लिए नहीं किया जायेगा।
- 10 प्लास्टिक फैटेरियल का उपयोग विनाईल ऐसेटेट-मारीफ एसिड, विनाईल बलोराइड, कोपालिमर सहित किसी भी रूप में नहीं किया जायेगा।

अध्याय-3

प्लास्टिक सीट/मल्टीलेयर पैकेजिंग का मार्किंग या लेबलिंग-

- 6 (i) खुदरा विकेता या स्ट्रीट बैंडर प्लास्टिक की सीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग में वस्तुओं को ग्राहक को नहीं देखने या संपर्क करने जो इस रूप विधि के अधीन यथा विवित रूप में विनिर्मित और लैबल या मार्क न किया गया हो।
- (ii) वस्तुओं को मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट से थरो कवरों में जो इस रूप विधि के अनुसार विनिर्मित या लैबल या मार्क न किये गये हों विक्रय या उपलब्ध करने वाले प्रत्येक खुदरा विकेता या स्ट्रीट बैंडर ऐसी फीस गुगतान करने का उत्तरदायी होगा जो उप विधि के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये हों।
- (iii) मल्टी लैबल पैकेजिंग पर विनिर्माता का नाम, निवन्धन सं0 मल्टीलेयर पैकेजिंग की दशा में अंगेजी में मुद्रित होगा।

अध्याय-4

उत्पादक, रिसाईनलर और विनिर्माता का निवन्धन

- 7(i) नियम 5 (ii) में किये गये प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक कैरी बैग या रिसाईफिल प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण नहीं करेगा तथा प्रावधान के अनुसार प्लास्टिक फैब्रिक राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से उत्पादन आरक्ष करने के पूर्व एक विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है।

(ii) प्लास्टिक मैटेरियल, मल्टीलेवर पैकेजिंग के सभी उत्पादक रिसाईकलर एवं विनिर्गता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन और नवीकरण प्राप्त करेगे।

अध्याय-5

प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण

8. प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण पृथक्करण एवं प्रसंस्करण नियन्त्रण किया जायेगा-

(क) शहरी स्थानीय निकाय अपने संसाधनों से प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन और प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्करण को कम करने हेतु फदम उठायेगी

(ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के स्थितावधि को कम करने तथा सेफेल्डी स्टोरेज डिपो/समुदायिक बस्टबीन पर अपशिष्ट के मूलक किये गये अपदारण के लिए कवग उठायेगी प्लास्टिक अपशिष्ट केवल नॉन बायोडिग्रेडेबल या ड्राई वेस्ट बिन में ही प्रक्रिया किया जायेगा।

(ग) सेफेल्डी स्टोरेज पॉइंट/डिपो/ट्रांसपोर्ट स्टेशनों पर शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट उठाने वालों तथा अन्य सामाजिक आयोजनकार्ताओं को प्लास्टिक गिलास तथा कागजों को रिसाईकिंग एवं मुनः उपयोग के लिए ग्रौन्साइट करेगी अनीपचारिक अपशिष्ट उठाने वालों को ड्राई रिसाईकलेबल अपशिष्ट को संग्रह करने तथा प्राथिकृत रिसाईकलर्स को उसे बेचने की स्वीकृति भी उनकी जीविका को उपार्जन के लिए जीधे दी जायेगी।

(घ) शहरी रथानीय निकाय गीला एवं सूखा फूड के पृथक्करण के इनसे मैटेरियल के साधन, रीटेरियल रिफलरी सुविधा की स्थापना के माध्यम से पेगर, जॉहा, शीशा, ई बेस्ट, पालीयीन, चमड़े, जूते, पेट बौद्धन इवर इत्यादि जैसे ड्राई वेस्ट के भण्डारण एवं खटाई के लिए अलग बीन या भण्डार की व्यवस्था के साथ सुनिश्चित करेगी।

(ङ) शहरी स्थानीय निकाय आवश्यकताओं/स्थानीय हालात के अनुसार अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्ध तकनीकी जैसे- प्लाज्मा गाइड्रोला द्वारा राक्तान्की, बेलिंग प्रेस और रिस्पूज ब्रॉडबैंड फ्लूल (आर.डी.एफ.) निर्माण, सीमेट क्लो तथा प्लास्टिक ब्रेडिंग को-प्रोसेसिंग भी स्थापना की भी जांच पड़ताल करेगी।

(ज) शहरी स्थानीय निकाय कवरे चुनने वालों की उनका उपयोग एम.आर.एफ. और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा में करके कायाएजट की सक्तीय कम से कार्य करेगी।

(झ) शहरी स्थानीय निकाय अनीपचारिक ब्रेट पिक्स/फ्लाडी वाले एवं एस.एच.जी. के लिए स्वास्थ्य के मुद्दों, जीविका तथा आय स्थानक क्रियाकलापों पर अग्राही संवेदना ग्रह, सेवन श्रीभाग आयोजित करेगी।

(झ) दोकेश्वर विद्यालय जैसे पेपर दैग अभ्यास, कार्टन बैग, लिलाई, कूशन मेंकिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देने का कार्य भी करेगी।

अध्याय-6

9. मोनिटरिंग किया विधि

(क) इन उप विधियों के प्राविधानों के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर पंचायत के अधिकारी अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस नियमित हेतु इसके सदस्य अधिकारी अधिकारी द्वारा नामिन किये जायेंगे।

अध्याय-७

उपयोग कर्ता फीस तथा जुर्माना

10- प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह, प्रवर्तन और प्रबन्धन के लिए उपयोगकर्ता फीस का लागू होना शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपयोग के अनुसार संग्रहित उपयोगकर्ता फीस का 15 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के प्रयोजनार्थ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

11 उल्लंघन पर जुर्माना

(क) इस उपयोग के आरम्भ की तिथि को छोर उसके बाद पर्यावरण धन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रकाशन अधिसूचना के अनुसार एक भाह तक जन साधारण को जानकारी/चेतावनी दी जा सकेगी जिसके बाद इस उपयोग का कोई उल्लंघन अनुसूची-1 में यथाविहित जुर्माने से इस उपयोग के भंग के प्रत्येक अवसर पर दण्डनीय होगा।

(ख) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट बैंडर शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में किसी वस्तु को देने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग उपलब्ध करते हुए प्राया जाता है तो शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची-1 में यथा विनियिह जुर्माना अद्विरोधित करेगी।

(ग) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट बैंडर वस्तुओं को प्लास्टिक कैरी बैग या प्लास्टिक के बगे गल्टीलेयर ऐकेजिंग या प्लास्टिक बीट या कवर में जिसका विनिर्माण लेवल या मार्क उपयोग के अनुसार नहीं किया गया हो विकल्प या उपलब्ध करता है तो प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची- 1 में यथा विनियिह जुर्माना मुगलाज करने का उत्तरदायी होगा।

(घ) नगर पालिका परिषद् अधिनियम के अंतर्गत भगर पेंचात के अधिकारी उपयोगियों के प्राविधानों के उल्लंघनकर्ता से स्पॉट पर जुर्माना बहुम करेगे।

12- अविकल की दशा में नार्यसाक्षी -

कोई विनिर्माता, उत्पादक, आमातक, स्टाफिस्ट, होल्डेलर, रिटेलर, दुकानदार, स्ट्रीट बैंडर जो जुर्माना नहीं देगा वह गम्भीर कर के खकाये के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा बस्ती के लिए उत्तरदायी होगा बार-बार अपराध करने वालों के चिरूद्ध भगरपालिका अधिनियम के प्राविधानों/स्थापित नियमों के अंतर्गत कार्यवही की जायेगी।

अध्याय-८

अविदेशी का वार्षिक रिटैन

13- आवेदन तथा वार्षिक रिटैन (पी.एन्जु.एम. नियमावली 2016)

(क) प्रत्येक उत्पादक रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण प्रयोजनार्थ, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुसार फार्म-1 में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(ख) अपशिष्ट (वैस्ट) रीसाइकिलग या प्रोसेसिंग करने वाला अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट का रिसाईकिल या प्रोसेस का प्रसंरकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति रीसाइकिलग यूनिट के रजिस्ट्रेशन अथवा रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुसार फार्म में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(ग) उत्पादक द्वारा कंधा भाज के उपयोग किये जाने हेतु शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में प्लास्टिक के विनियोग में लगा प्रत्येक विनिर्माता रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए फार्म-1 में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट के रीसाइकिलग एवं प्रोसेसिंग में लगा प्रत्येक व्यक्ति फार्म- V में एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की जानकारी में शहरी स्थानीय निकाय को समर्पित करेगा।

(इ) नगर पंचायत केलाखेड़ा फार्म-V में वार्षिक व्रतिवेदन सैयाद करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को रामणित करेगा।

अध्याय-9

स्टॉक होस्टिंग का उत्तरदायित्व :

14.1 नगर पंचायत केलाखेड़ा का उत्तरदायित्व :

(क) शहरी स्थानीय निकाय स्वयं के खर्च पर अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के भाष्यम से एजेंसियों या उत्पादकों को संग्राकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण प्रणाली परिवहन, प्रोसेसिंग तथा निपटारे के लिए आधारभूत संरचना विकसित करेगी।

(छ) शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के समन्वय तथा शहरोंजित मूल्यों के पालन के लिए जिम्मेदारी होगी, यथा-

1. प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, प्राणारण, परिवहन प्रोसेसिंग तथा निपटारे को सुनिश्चित करना।
2. इस प्रोसेसिंग के दौरान यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो,
3. रिसाईफिल्स को रिसाईफिल्स प्लास्टिक अपशिष्ट छण्ड का चैनलाइजेशन सुनिश्चित करना।
4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट ने गैर- रिसाईफिल्स खण्ड के प्रोसेसिंग तथा निपटारे को सुनिश्चित करना।
5. सभी स्टॉकहोस्टिंगों के बीच उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
6. वेस्ट पिकर्स के साथ सिविल सोसाईटी या समूह को कामिन्न करना।
7. यह सुनिश्चित करना प्लास्टिक फोंसुले में न जलाया जाय।

(ग) शहरी स्थानीय निकाय स्वयं या किसी एजेंसी को संग्राकर प्लास्टिक अपशिष्ट भेदभाव केन्द्रों की स्थापना, करेगी। जहाँ भोई अपशिष्ट उत्पादक संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगी जहाँ कोई अपशिष्ट उत्पादक या वेस्ट पिकर्स सीधा प्लास्टिक अपशिष्ट को जमा कर सके। यह प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण के खोल, खुले में जलाने पर रोक इत्यादि की जानकारी फैलाने तथा राष्ट्रीय प्रहृष्ट के लिए भी एक स्थान होगा।

(घ) शहरी स्थानीय निकाय अपनी अधिकारी द्वारा केन्द्र में प्लास्टिक का अस्थायिक उपयोग करके समस्या उत्पन्न करने, पर्यावरण पर प्लास्टिक के अस्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रभाव, प्लास्टिक के बदले गैर प्लास्टिक इत्यादि पर जागरूकता जागरूकता पैदा कर प्लास्टिक उपयोग को कम करने प्रोत्साहित करेगी और उसके लिए वजट का प्रावधान करेगी।

(इ) जुमनि के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संपह की गई निधि पृथक खाते में रखी जाएगी और अपनी अधिकारिता के भीतर तकसम्बन्धी आधारभूत संरचना तथा सब तरह से अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के धोखणा के लिए उपयोग की जाएगी।

(च) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रणाली स्थापित करने के लिए विनिर्दिमाताओं उत्पादकों तथा इन स्थायियों की सहायता लेगी।

14.2 अपशिष्ट उत्पादक की जिम्मेदारी

(क) अपशिष्ट उत्पादक निम्नलिखित कार्य होंगे-

(1) प्लास्टिक अपशिष्ट कम तथा लोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 (समय-समय यथा संशोधित) के अनुसार खोल पर ही प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करना तथा इसे गैर वायोडिगेडेल अपशिष्ट के लिए बने बिन में संग्रह करना।

(૧) પ્લાસ્ટિક કૂડા-કચરાન ફેલાના તથા સ્વોત પર હી અપશિષ્ટ પૃથક્કૃત ભણ્ણારણ સુનિશ્ચિત કરના એવ રજિસ્ટર્ડ વેસ્ટ પિકર્સ રજિસ્ટર્ડ રિસાઈનલર્સ થા વેસ્ટ સંગ્રહણ કે લિએ શાહીરી સ્થાનીય નિકાય દ્વારા વેસ્ટ સંગ્રહકર્તા યા પ્રાધિકૃત એજેન્સી કો હૃત્સતગત કર દેના

(૨) પ્લાસ્ટિક અપશિષ્ટ કે સભી સંસ્થાગત ઉત્પાદક ટોસ અપશિષ્ટ નિયમાવસી 2016 (સમય-સમય પર થથા સંશોધિત) કે અનુસાર અપશિષ્ટ ઉત્પાદિત અપશિષ્ટ કો પૃથક કરેંગે દ્વારા જમા કરેંગે

(૩) સભી અપશિષ્ટ ઉત્પાદક પ્લાસ્ટિક અપશિષ્ટ પ્રબન્ધન જેસે અપશિષ્ટ સંગ્રહણ મા પ્રવર્તન યા ઉસી સુવિધા ઇત્યાદિ કે લિએ ફીસ થા શુલ્ક મા ભુગતાન કરેંગે જો ઇસ હેતુ નગર મંચાયત દ્વારા ટોસ અપશિષ્ટ પ્રબન્ધન નિયમાવસી 2017 કે અનુસાર મેં વિનિર્દિષ્ટ ફી જાય।

(૪) શુલી જગ્હ મેં કોઈ સમારોહ આયોજિત કિયે જાને યા એક સી સે અદ્ધિક અંતિમીયોં કો એક જગ્હ જમા કરતે જિસમે પ્લાસ્ટિક થા મલ્ટીલેયર પેકેજિંગ મેં યોજાના સામગ્રી દેના બાતિશસ્ત હો કે લિએ જિમ્મેવાર પ્રત્યેક બ્યાંકિંગ એસે સમારોહ કે વીરાન ઉત્પાદિત અપશિષ્ટ કો પૃથક કરેણ બીર પ્રસ્ત્રનિધિસા કરેણા। એસે સમારોહ કાર્ય આયોજાગ સે કમ સે કમ તીન કાર્ય ચિન પૂર્વ શાહીરી સ્થાનીય નિકાય થો સુખિત કરના ચાહ્ના તથા શાહીરી સ્થાનીય નિકાય દ્વારા થથા નિયત કૈનિક રેટન ચાર્જ કા સુગતાન કર વૈસે પૃથક્કૃત અપશિષ્ટ કે ભણ્ણારણ કે નિય 1 ૧ કર્ણ રીઓ કા થો કી સંખ્યા મેં કન્નેનર રખતે હેતુ નગર મંચાયત કેલાંદોના સે અનુરોધ કિયા જાના ચાહ્ના।

14.3 ઉત્પાદક આયાતક ત્રણ બ્લોંડ માલિક કે ઉત્પાદાયિત :-

(અ) ઉત્પાદક ઉપ વિધિ કે પ્રકાશન કી તિથિ સે ૬ માટ્ટ કી સમયસીમાન કે ભીનર વિસ્તારિત ઉત્પાદક ઉત્તરદાખિત આધારિત અપશિષ્ટ સંગ્રહણ પ્રણાસી કે લિએ મૌંડલિટી તૈયાર કરના ત્રણ નિદેશક શાહીરી ચિકાસ નિદેશાલય ઉત્તરાખણ કો અંતિગૃહ કપ રો સામૂહિક રૂપ રો અને વિતરણ નેના થા કસ્યાનિધિ સ્થાનીય નિકાય કે માદ્યદસ સે જસે અન્તરિત કરેણે।

(બ) ઉત્પાદક રાજ્ય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ સે રજિસ્ટ્રીકૃત હોંગે

(ગ) સભી ઉત્પાદક, બાન્ડ માલિક થા આયાતક જો મલ્ટીલેયર પ્લાસ્ટિક શીટ થા પાઉન્ડ થા પેકેજિંગ ઇત્યાદિ કા ઉપયોગ કરતે હુએ અપને ઉત્પાદો કા વિકય વિષણન કરતે હુએ અને ઉત્પાદો કે ચલતે ઉત્પાદિત અપશિષ્ટ કો વાપસ ભાગ્ય કરતે કી પણાસી સ્થાપિત કરતે કે લિએ પ્રાથમિક શરૂ સે જિમ્મેવાર હોંગે।

(ધ) ઉપયોગ કિએ ગાએ મલ્ટીલેયર પ્લાસ્ટિક સેચેટ થા પાઉન્ડ થા પેકેજિંગ કે સંગ્રહણ કી પ્રાથમિક જિમ્મેવારી ઉત્પાદકો, આયાત થો બીર સાન્ધ સ્વામિયોં કી હૈ, જો બાજાર મેં ઉત્પાદો થો ઉત્પાદાયિત કરતો હૈ ડનકે ઉત્પાદો કે ચમત્રે ઉત્પાદિત પ્લાસ્ટિક અપશિષ્ટ ધાપાન સંગ્રહ કરતે હેતુ કોઈ પ્રણાસી સ્થાપિત કરના ડનકી આદ્યયકતા હૈ। યાહુ સંગ્રહણ યોજના સ્થાપના થા પ્રબર્તન યા નવીનીકરણ હેતુ સહ્યમતિ કે લિએ આદ્યયક કરતે સમય રાજ્ય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ કો સમર્પિત કરની હૈ।

(ઘ) પ્રત્યેક ઉત્પાદક કષ્ટે માન કે રૂપ મેં પ્લાસ્ટિક શીટ થા ઇસી પ્રકાર બસ્તુ થા પ્લાસ્ટિક શીટ થા મલ્ટીલેયર પેકેજિંગ કે બને કન્ને કન્ને કે નિર્માણ હેતુ પ્લાસ્ટિક બી બાપૂર્તિ મેં લગે અંતિમીયોં કે બ્યારે કા એક અભિજોખ સંધારિત કરેણા।

(ઝ) પ્લાસ્ટિક કા ઉપયોગ કરતે હુએ રિસાઈન્લેયલ મલ્ટીલેયર ત્રણ પેપર આપારિત કાર્બન પેકેજિંગ સામગ્રી કે બિનિર્માચા/બ્લોંડ માલિક, ઉત્પાદક અપની વિસ્તારિત ઉત્પાદક ઉત્પાદાયિત (ઇ.પી.આર.) યોજના જિસમે પ્લાસ્ટિક અપશિષ્ટ કે સંગ્રહણ કે લિએ વિદ્યમાન વેસ્ટ વર્કેસ/સ્ક્રીપ ટ્રેસર્સ, રિટેલર્સ, કે સાથ સમન્વય/સહ્યોગ બીર ડનકે સ્વંચ સ્થાપિત રિસાઈન્નિંગ પ્લાંટ થા ઉત્પાદક ઉત્તરદાયી સંગઠન (પીઓગાર્ડો) સ્થાપિત કરકે રજિસ્ટર્ડ રિસાઈકિલર્સ જો અભિજો પ્લાસ્ટિક અપશિષ્ટ પ્રબન્ધન સંગ્રહણ સે મંત્રિમ નિયંત્રણ તક ૨૦૦ પ્રતિશત જિમ્મેવાર હોંગે, કર્મચારા જિન્યાન્ચિત કરેંગે।

(ઝી) ફી ઈ ટી બોટલ (P.E.T. BOTTLE) ઉત્પાદકો/ઉદ્યોગોનો કો યા સુનિશ્ચિત કરને કી પૂર્વ જિમ્મેવારી હોગી કે ઉત્પાદકોને દ્વારા થથા વિનિશ્ચિત વાપસી દર થા ખરીદ વૈન્ક દર પર રિટેલર્સ સે ઇન બોટલોનો કા સંગ્રહણ કિયા જાય, બીર વાપસી/ખરીદ વૈન્ક કી કીમત સ્પષ્ટ રૂપ સે મુદ્રિત કરતે કી જિમ્મેવારી ઉત્પાદકો કી હૈ।

(જ) વહુસંખ્યા મેં પી ઈ.ટી. બોવલ ઉપમોક્તાઓ જેસે હોટલ, મૈરિઝ હોલ/પાર્ટી હોલ, બાહ્ય ખેલ, સ્થાનો કાયાલિયો/સંસ્થાઓ કી પ્લાસ્ટિક અપશિષ્ટ કે સંગ્રહણ કે શિએ ઉપલબ્ધ કરના ઉનકે લિએ આજાપક હોણા

(ઝ) રિટેલ પૈકેજિંગ મૈટેરિલ કે લિએ વિનિર્મિતા સંપર તથા રિટેલર કે બચ્ચીદ બૈક ક્રિયા વિધિ કે માણયમ સે ગ્રોસરીઝ એવ અમાવા કે પૈકિંગ કે લિએ ઉપયોગ કિએ ગાએ પ્લાસ્ટિક પૈકિંગ કે લિએ ઉપયોગ કિએ ગાએ પ્લાસ્ટિક પૈકેજિંગ સામગ્રીઓ કે સંગ્રહણ એક ક્રિયા વિધિ સુજિત કરકે સામૂહિક રૂપ સે કાર્ય કરેં તથા સંગ્રહ કી ગઈ પ્લાસ્ટિક સામગ્રીઓ કા રિસાઇકલ કરના તથા નિપટારા કરના સુનિશ્ચિત કરેં

14.4 રિટેલર્સ સ્ટ્રીટ બેંદર, બાને વાનો/હોકર ઇલાદી કી જિન્સેવારી -

(ક) દુકાનદાર, બેંદર, થોક વિકેતા, રિટેલ બેંદર બાને વાસે હોકર, ફેરીબાલા યા સંભ્રાનીબાલા સહિત કોઈ સી જ્વાંસ બાને યોગ્ય થા ન બાને યોગ્ય માલ યા સામગ્રીઓ કે અણદાર વિતરણ કે લિએ કિસી બી પ્રકાર કે કેરી થૈંગો કા વિકાપ પ્રણદારણ યા વિતરણ યા ઉપયોગ નહી કરેણા

(લ) પ્લાસ્ટિક કેરી બૈગ કા દુકાનદાર/વિકેતા રિટેલર યા ટ્રેન્સી, પર્યાવરણ વન એંચ ખલબાયુ પરિવર્તન વિમાગ ઉત્તરાખણ્ડ સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત અધિસૂચના કે દિનાંક સે સમય સીમા કે મીતર ઉદ્યોગ વિકાય સ્ટોક સમાસ કર દેંગે, ઉસ કાલાવાંશી કે બાદ કિસી એસે પ્લાસ્ટિક કેરી થૈંગ વિકાય ખણ્દારણ યા ઉપયોગ ઇસુ ઉપવિધિ કી અનુસૂચી-૧ કે અધીન યથા વિનિર્દિષ્ટ શુમની કે અધીન હોણા

(ન) માટ્ટીલેયર પૈકેજિંગ યા પ્લાસ્ટિક શીટ યા ઇસ પ્રકાર નસ્તુ યા પ્લાસ્ટિક શીટ કે બને ફલારો, જો ઇસ નિયમાબદી કે અનુસાર વિનિર્મિત યા દેવલ ન ક્રિયા ગમા હો, બસ્તુઓ કો બેચને બાના થા ઉપલબ્ધ કરને બાલા પ્રત્યેક રિટેલર યા સ્ટ્રીટ બેંદર ઇસ ઉપવિધિ કી અનુસૂચી-૧ કે અધીન યથા વિનિર્દિષ્ટ શુમની કે મુગરાન કા દોષી હોણા

14.5 શ્રાવ્ય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (પસ.પી.ભી), ઉત્તરાખણ્ડ શાસન ની જિન્સેવારી :-

(ક) રાજ્ય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદો કે વિનિર્માણ તથા મલ્ટીલેયર પૈકેજિંગ, પ્રોસેસિંગ થોર પ્લાસ્ટિક અપશિષ્ટ કે નિપટારે સે સમબન્ધિત ઇસ નિયમાબદી કે પ્રાવિધાનો કો લાગ્યુ કરને હેતુ પ્રાથિકાર હોણા

(લ) રાજ્ય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, ઉત્તરાખણ્ડ શાસન પ્લાસ્ટિક અપશિષ્ટ નિયમાબદી 2016 કે ક્રિયાન્વયન પર એક વાર્ષિક રિપોર્ટ તૈયાર કરેણા થોરા થોરા પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ કો સમર્પિત કરેણા

14.6 જિલ્લા સ્થાનીય સુરીયા પંચ મોનિટરિંગ સમિતિ :-

(ક) ઠોસ એંધ પ્લાસ્ટિક ક્રાફ્ટ પ્રબન્ધન ક્રિયાકાલાપો દે સમબન્ધિત કાર્યો કી સમીક્ષા એવ મોનિટરિંગ કરના

(લ) થોસ અપશિષ્ટ એંધ પ્લાસ્ટિક અપશિષ્ટ કા બેસલાઇન હેટા બેસ તૈયાર કરને તથા વિષિસ્ટ વિસ્થારણ કરને હેતુ શહૂરી સ્થાનીય નિકાયો કો નિર્દેશ દેણા

(ઘ) થોસ અપશિષ્ટ/પ્લાસ્ટિક પ્રબન્ધન અભિયાન કી પ્રગતિ કા મોનિટરિંગ કરના થોરા અને યાચાચશ્યક સામાયિક સુધાર કરના તથા નિયમિત સમીક્ષા કરના એવ નગર વિકાસ એંધ બાવાસ નિયમ તથા અન્ય રાજ્ય સમન્વય એઝેસીઓ કે રાય સમન્વય સ્થાપિત કરના

(દ) શહૂરી સ્થાનીય નિકાય કે થોસ અપશિષ્ટ પ્રબન્ધન એવ થોસ અપશિષ્ટ પ્રોસેસિંગ વિસ્થોજલ સુવિદ્ધા સ્થાપિત કરને કે લિએ ઉપયુક્ત ભૂમિ કી પહૂનાન થીર સ્થાન મિર્દારિણ પર તીન માત્ર પર કમ સે કંગ એક બાર શહૂરી સ્થાનીય નિકાય કે કાર્યપાલક બી સમીક્ષા સમી સમિતિ કરેણી

(ચ) વાર્ધ સ્વચ્છતા સમિતિ, સહાયક સંગઠન, જાઈન સિટ્સાગો તથા સિવિલ સોસાઈટી સંગઠનો કે સાય પ્રગાહી સ્થાપિત કરને મે જો ઠોસ તથા પ્લાસ્ટિક અપશિષ્ટ કે સામુદ્દરિક સ્તર પર મોનિટરિંગ તથા પ્રબન્ધન કરને કા સમર્થન કરને કે સમન્વય સે સીદા નિર્દેશ દેણી થીર કાર્ય કરેણી

(ઝ) શહૂરી સ્થાનીય નિકાય કે પરામર્શ સે વાર્ધ સ્થાનીય મોનિટરિંગ કે લિએ કિસી સમિતિ/ઉપસમિતિ કો ઉત્તરદાયિત્વ સીદેણી

14.7 स्कूल/टास्कफोर्स की जिम्मेदारी सिटी स्कूल/टास्कफोर्स नियमित्तित कार्यों का जिम्मा/लेशा-

(क) नगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न दुकानों भोजनालालों, मज़बीबालों तथा वाणिज्यक दुकानों में अचानक निरीक्षण का संचालन करना और इन व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैगों को जब्त करना।

(ख) प्रतिबंधित पौसिथीन पैकेजिंग मैटेरियल सथा ५० भाइक्रोन से कम मोटाई वाला जीर जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावधी २०१६ में किए गए प्राविधानों के अनुसार सेबस अथवा मार्क नहीं किए गए हो सहबद्ध उत्पादों को जब्त करना।

(ग) इस उपक्रिया की अनुसूची-१ में विहित व्यक्तिगतियों से जुर्माना यसूल करना।

(घ) नगर प्लास्टिक कैरी बैगों अंतराज्य संचालन तथा विकल्प की रीकाना।

(ङ) नगर प्लास्टिक कैरी बैगों का किसी कानून के क्षेत्र से किसी व्यक्ति/व्यवसायी/स्टार्किट को बेचने से रोकना।

अनुसूची-१

क्र० सं०	अपराध	प्रशमन चार्ज		
		प्रथम बार	द्वितीय बार	प्रत्येक बार दुहराए जाने पर
१	मोटाई और आकार का विचार किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण स्वास्थ्य, भण्डारण विक्रय	२०००	३०००	५०००
२	प्लास्टिक फैरी बैग का उपयोगकर्ता			
३	सार्विक उपयोगकर्ता	१५००	२५००	३५००
४	बरेहू उपयोगकर्ता	१००	२००	५००
५	महत्वीपेय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐरी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बने भवर जो प्लास्टिक अपरिहृष्ट प्रबन्धनों के अनुसार विनियमित लेवल या भारी नहीं किए गए हैं, जो वस्तुओं का उपयोग विक्रय या उसे उपलब्ध करना।	२०००	३०००	५०००
६	प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले भैंसाना	२०००	३०००	५०००
७	सार्वजनिक स्थानों पार्क, नाला पुरातात्त्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों में प्लास्टिक अपशिष्ट का फेलाना	१०००	१५००	२०००
८	शहरी स्थानीय निकाय को सूचना दिए बिना इस उपयित्र के अनुसार व्यवस्था किए बिना कोई समाप्ति या समावेशी या एक सी से अधिक व्यक्तियों द्वारा जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति	१५००	२०००	२५००

इस उपयित्र के प्रविधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति (मिर्ता, उत्पादक, आयातक, खुदरा विक्रेता, सड़क विक्रेता, स्टाकिट इत्यादि) के साथ पाए गए प्रतिबंधित सामान इस उप-कानून के प्रविधानों में उल्लिखित अनुसार जब्त कर लिया जायेगा।

फॉर्म - IV

(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली २०१६ का)

(नियम १७(१)के अधीन)

स्थानीय निकाय के नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसिंग या रिसाईकिलिंग सुविधा के ऑपरेटर द्वारा समर्पित किए जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र।

क्र० स०	रिपोर्ट की कालावधि	
१	सुविधा ऑपरेटर का नाम और पता	
२	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम	
	टेलीफोन	
	फैक्स	
	मोबाइल	
	ई-मेल	
३	हृसियत	
४	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिए उपयोग की जानेवाली प्रौद्योगिकी	
५	वर्ष के दौरान ज्वोत के साथ-साथ रिपोर्ट की जानेवाली प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा	
६	प्रत्यक्ष प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
७	मूमि को भरने वाले स्थल पर अंतिम निपटारे के लिए देणी गई निष्क्रिय या अस्वीकृत मात्रा	
८	फार्म भरने की सुविधा का व्यौरा जिसके अंतिम निपटारे के लिए निष्क्रिय या अस्वीकृत भेजे गए थे	
	पता -	
	टेलीफोन -	
९	पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की स्थिति यदि सहमति या रजिस्ट्रेशन मंजूरी के दौरान विनिर्दिष्ट किया गया हो सलंग किया जाय।	
	दिनांक:	
	स्थान:	ऑपरेटर का हस्ताक्षर

फॉर्म - V

(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 का)

(नियम 17 (2) के अधीन)

शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी सचिव को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर किए जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र।

क्र० सं०	रिपोर्ट की कालावधि
1	नगर, शहर और राज्य का नाम
2	जनसंख्या
3	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र
4	शहरी स्थानीय निकाय का नाम और पता- टेलिफोन संख्या- फैक्ट्र संख्या- ई-मेल-
5	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में बाजारों की कुल संख्या
6	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में मकानों की कुल संख्या
7	डोर-टू-डोर संचाहण द्वारा आच्छादित मकानों की संख्या
8	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वाणिज्यिक स्थापनाओं और संस्थाओं की कुल संख्या
9	घारिजाह घारिजाह संस्थाएं
10	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए रखे गये यंत्र के साथ-साथ डोर-टू-डोर संचाहण के लगी एजेंसियों के बाहरे का संक्षिप्त विवरण
11	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए स्थान पर लगाए गये आदारभूत संरचना का व्यौरा सलंग करें।

12	अपेक्षित आधारभूत संरचना या व्यौरा औचित्य के साथ-साथ यदि कोई हो, सलंग करें।	
13	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
14	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान संस्थ किये गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
15	वर्ष के दौरान रिसाइकिंग के लिए चैनल कूत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
16	वर्ष के दौरान उपयोग के लिए चैनल कूत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
17	वर्ष के दौरान मूभि भराई स्थल को बेजे गये निष्क्रिय या अस्वीकृत मात्रा (टनों में)	
18	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रोसेसिंग और निपटारे के लिए उपयोग की गई प्रत्येक सुविधा का व्यौरा	
	सुविधा-I	
	ऑपरेटर का नाम	
	पक्षा-	
	टेलिफोन या मोबाइल संख्या-	
	कामता-	
	उपयोग की गई प्रौद्योगिकी -	
	रजिस्ट्रेशन संख्या	
	रजिस्ट्रेशन की विशिमान्यता तक-	
	सुविधा- II	
	ऑपरेटर का नाम	
	पक्षा-	
	टेलिफोन या मोबाइल संख्या-	
	कामता-	
	उपयोग की यही कामता-	
	रजिस्ट्रेशन की विशिमान्यता तक-	

19	ગલી મેં ઝાડૂ લગાને, સેકેન્ડરી બાણ્ડાર પરિવહન, પ્રોસેસિંગ તથા અપશિષ્ટ કા નિપટારા સહિત શહરી સ્થાનીય નિકાય કે સંબંધ કે દ્વારા ફેલાઈ ગઈ માનવ શક્તિ કા બ્યૌદ્ધ દેંને।	
20	ગલી મેં ઝાડૂ લગાને બાણ્ડાર પરિવહન, પ્રોસેસિંગ તથા અપશિષ્ટ કા નિપટારા સહિત સંગ્રહણ કે લિએ ઠેકેદાર રિયાયત ગ્રાહી બ્યક્સિ દ્વારા ફેલાઈ ગઈ માનવ શક્તિ કા બ્યૌદ્ધ	
21	વિક્ષીય દવાબ, ચાદિ કોઈ હો, સહિત ઇસ નિયમાબલી કે પ્રાવધાનોને કે અતુપાત્ન મેં શહરી સ્થાનીય નિકાય દ્વારા અનુભવ કી ગઈ કાઠિનાઈયોં જી સંકોચ મેં વર્ણન કરોણે।	
22	ક્ષ્યા નગર મેં કોષ અપશિષ્ટ પ્રવન્ધન કે ઉપાયોં કો વિકસિત કરોણે કે લિએ કાર્ય યોજના બનાઈ ગઈ હૈ, ચાદિ હો (પ્રતિલિપિ સહંગ કરોણે) પુનરીબાન કી તિથિ-	

રાજ કુમાર ભારતી,
અધિશાસી અધિકારી,
નગર પંચાયત કેલાખોડા,
ઊંઘસ સિંહ નગર।

અકરમ ખાન,
અધ્યક્ષ,
નગર પંચાયત કેલાખોડા,
ઊંઘસ સિંહ નગર।